

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2001/फाल्गुन 9, 1922

No. 57]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2001/PHALGUNA 9, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिरुचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2001

सं. 15(5)-बी (डी)/2001.—मिम्बलिखित को संप्रसाधारण के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2001-2002

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा का भाषण

28 फरवरी, 2001

भाग क

मान्यवर,

मैं वर्ष 2001-2002 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. यह मेरा दिनभरापूर्ण प्रस्तुतीकरण है। इस वर्ष हम गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के भूकम्प से उत्पन्न त्रासदी एवं विनाश ने इन चुनौतियों को और भी भयंकर बना दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इन चुनौतियों का सामना करने के मेरे प्रयत्न को पूरे सदन की सहानुभूति एवं समर्थन मिलेगा।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

3. भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत कुछ वर्षों के निष्पादन की तरह विकास एवं उभरने की शक्ति दोनों मौजूद हैं। अनेक अप्रत्याशित गतिरोधों के बावजूद इस वर्ष समग्र आर्थिक विकास लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। लगातार दूसरे वर्ष में भी मानसून अनियमित रहा है जिससे कृषि विकास में कमी आयी है। विश्व में पैट्रोलियम की कीमतें ऊँचे स्तरों पर बनी रहीं जिससे अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से दबाव बना रहा और इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष में मुद्रास्फीति काफी बढ़ी है। सौभाग्य से ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद अनिवार्य वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतें समग्र रूप से स्थिर रही हैं। ऊर्जा को छोड़कर मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान लगभग 4 प्रतिशत थी, विदेशी मुद्रा रिजर्व और जन खाद्य भण्डारों के अच्छे रिकार्ड स्तर के कारण अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिली। पिछले वर्ष के सराहनीय निर्यात निष्पादन में और सुधार हुआ और अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में डालर के सन्दर्भ में निर्यातों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

4. 1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों को अब दस वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में वर्ष 1992-93 से प्रति वर्ष औसत 6.4% की दर से वृद्धि हुई है जो 1980 के दशक की 5.8% की तुलना में है। गरीबी का प्रतिशत 1993-94 में 36% से कम होकर अब 26% या इससे कम हो गया है।

5. जहाँ आर्थिक सुधारों ने देश को काफी अधिक सुरक्षित और निरन्तर प्रगति की राह पर पहुंचाया है, वहाँ हमारी कुछ गम्भीर चिन्ताएं भी हैं और हम सन्तुष्ट होकर नहीं बैठ सकते।

- कृषि सुधार अपर्याप्त रहे हैं और हमारी कृषि को मानसून की असफलता निरन्तर झेलनी पड़ रही है।
- बड़े औद्योगिक क्षेत्र के सुधारों के बावजूद औद्योगिक विकास तेज होकर दशमांक तक भी नहीं पहुंच पाया है जैसी कि आशा की गयी थी।
- गत दशक में अपर्याप्त राजकोषीय समायोजन सर्वाधिक कठिन समस्या बनी रही है।
 - ब्याज भुगतान अब केन्द्र के कर राजस्वों के 69 प्रतिशत से अधिक है।
 - सब्सिडियां अवहनीयता के स्तरों तक लगातार बढ़ती जा रही हैं और वह पात्र लाभार्थियों तक पहुंच भी नहीं पाती हैं।
 - सरकार की पेंशन देनदारी बोझिल होती जा रही हैं।
- कुल सरकारी क्षेत्र की बचतों में गिरावट के कारण आधार सुविधा एवं सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश अपर्याप्त है।
- ऊंची मौजूदा ब्याज दरों और अपर्याप्त आधार सुविधा के कारण निजी निवेश अवरुद्ध है।

बजट कार्यनीति

6. इस प्रकार पिछले दशक में आर्थिक सुधारों की अनेक उपलब्धियों के बावजूद हमें अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए अभी काफी कुछ करना है। अगले दशक में अधिक वृद्धि का वातावरण तैयार करने के लिए सुधारों को और तेज करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे बढ़ते हुए भारी ऋणों का बोझ हमारी आने वाली पीढ़ियों पर न पड़े, इसके लिए राजकोषीय समायोजन में हमें अपने प्रयत्न बढ़ाने हैं। पिछले 20 वर्षों में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से तेजी आयी है। अगले 20 वर्षों में इससे भी अधिक वृद्धि प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा होनी चाहिए।

7. अतः वृद्धि के इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट कार्यनीति को निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- कृषि क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाना और खाद्य अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबन्धन।
- आधारभूत सुविधा निवेश में वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रों और पूंजी बाजारों में निरन्तर सुधार, आर्थिक क्रियाकलापों के लिये बाधक शेष बोझिल नियंत्रणों को हटाकर संरचनात्मक सुधारों को व्यापक बनाना।
- बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा मानव संसाधन विकास।
- अनुत्पादनकारी व्यय का सख्ती से नियंत्रण, सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना और सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- निजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन।
- कराधार बढ़ाकर और उचित एवं समान कर संरचना लागू करके राजस्व बढ़ाना।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

8. जैसाकि मैंने देखा है, कृषि क्षेत्रक के सुधार अपर्याप्त रहे हैं और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने पहले ही एक अपूर्व राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कर दी है।

9. कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्धता का प्रावधान महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारिता बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांस्थानिक माध्यमों से कृषि को कुल उपलब्ध ऋण इस वर्ष 51,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2001-2002 में इसके बढ़कर 64000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने की आशा है जो 24 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्रक के निरन्तर सुदृढ़ विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- 'नाबार्ड' के साथ 1995-96 में स्थापित ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि (आई.आर.डी.एफ) का प्रचालन ग्रामीण आधार सुविधा के उन्नयन में काफी सफल रहा है जिसमें अभी तक लगभग 1,84,000 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राज्यों की सहायता के लिए मैंने नाबार्ड द्वारा लगायी गयी ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से कम करके 10.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। आर.आई.डी.एफ VII की संचित निधि (कार्पस) अगले वर्ष 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की जाएगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड की नई स्कीम काफी सफल सिद्ध हुई है। वर्ष 1998-99 में इसे शुरू करने के वर्ष से लगभग 110 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मैं हमारे बैंकों से इस कार्यक्रम में तेजी लाने और अगले तीन वर्षों के भीतर सभी पात्र किसानों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए कह रहा हूँ।
- मैं बैंकों से यह भी कह रहा हूँ कि वह अन्य क्रेडिट कार्डों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करें जिससे आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए उनको क्रमशः अधिकतम 50,000 रुपए और 25,000 रुपए का बीमा लाभ दिया जा सके। किश्त की अदायगी की साझेदारी कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा की जाएगी।
- 'नाबार्ड' और 'सिडबी' से चालू वर्ष के दौरान, एक लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ने के लिए कहा गया है। 'नाबार्ड' अगले महीने के अन्त तक इस लक्ष्य को पार करने के लिए स्वयं अच्छी तरह तैयार है। मैं वर्ष 2001-02 के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों को 'नाबार्ड' से जोड़ने की आशा करता हूँ जिससे अतिरिक्त, 20 लाख परिवारों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। बंटाईदार और असामी कृषक भी इस स्कीम के पात्र होंगे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 'नाबार्ड' और भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक के द्वारा 40 करोड़ रुपए के अंशदान से 'नाबार्ड' में एक लघु वित्त विकास निधि की भी स्थापना कर दी गयी है।
- मैंने पिछले वर्ष 'नाबार्ड' को पूंजी अभिलाभ कर छूट बांड जारी करने की अनुमति दी थी। इससे 'नाबार्ड' को सामान्य से कम ब्याज दरों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाने में मदद मिली है जिससे इसकी निधि लागत में कमी हुई है, मैं नाबार्ड के लिए यह कर छूट जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

- 'नाबार्ड' में स्थापित जल संभरण विकास निधि के संसाधनों का उपयोग इन स्कीमों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने और जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वयन, संचालन और अनुसंधान के लिये किया जाएगा।

10. वर्ष 1999 में मैन खराब होने वाली सामग्रियों के लिए शीत-भण्डारों के निर्माण हेतु ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। अभी तक 'नाबार्ड' और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) ने 9.6 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिए 161 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, इन शीत भण्डारों की स्थापना के लिए सरकार 78 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब मैं ग्रामीण गोदामों को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों में उचित रूप से बढ़ोतरी की जाएगी। ऋणों के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक अदायगी अवधि होगी और सहकारिता बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर गोदामों का निर्माण करने में व्यक्तियों, सहकारी समितियों और अन्यो को सुविधा होगी।

11. इस स्कीम से छोटे किसानों को अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे वह अपने उत्पाद लाभकारी मूल्यों पर बेच सकेंगे। फसलों के भण्डारण के निधि पोषण के लिए 'नाबार्ड' का प्रस्ताव अपनी ब्याज दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत करने का है। विशेषकर छोटे किसानों को अपनी मजबूरन बिक्रियों से बचने में इस स्कीम से फायदा होगा।

12. कृषि पद्धतियों के विविधीकरण और आधुनिकीकरण से कृषि के लिये सहायता एवं विस्तार सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिये 'नाबार्ड' की सहायता से कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिक्स एवं कृषि-कारोबार केन्द्रों की एक स्कीम आरंभ की जाएगी। यह केन्द्र मिट्टी एवं सामग्री परीक्षण सुविधाओं एवं अन्य परामर्शी सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करेंगे। यह प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। 'नाबार्ड' के पुनर्वित्त के साथ बैंकों द्वारा इन केन्द्रों की स्थापना के लिये आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किये जायेंगे।

13. फसलों के विविधीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के द्वारा पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में फसल-उत्पादकता सुधारने की काफी संभावनायें हैं। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में भूमिगत जल संसाधन भी हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। 'पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये फार्म में ही जल प्रबंधन' पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु 61 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

14. सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष मेरे द्वारा घोषित 'पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास के लिये प्रौद्योगिकी मिशन' हेतु मैंने 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

ग्रामीण सड़कें

15. ग्रामीण लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना नामक एक नई स्कीम चलाने की घोषणा की थी। इसकी अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में, विशेषकर ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का

शुभारम्भ किया गया है। वर्ष 2001-01 के लिये 2500 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आबंटन प्रदान किया गया था। आगामी वर्ष के लिये मैं पुनः 2500 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूँ। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये डीजल-उपकर का 50% निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

16. यह एक चिन्ता का विषय है कि नियोजित विकास के 50 वर्ष बाद भी अभी लगभग 80,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण सुधारने के लिये उपायों का एक पैकेज शुरू किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अगले 6 वर्षों में अधिकांश शेष गांवों का विद्युतीकरण पूरा करना।
- प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये राज्यों को सहायता-विस्तार।
- दलित बस्तियों, जनजातीय एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के घरों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की ऋण सहायता बढ़ाना।
- तीव्रकृत विद्युत विकास कार्यक्रम के अधीन गांवों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना, आर.ई.सी. सहायित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण-तंत्र का विस्तार।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये आर.आई.डी.एफ. से कम से कम 750 करोड़ रुपए की धनराशि का निर्धारण।
- आर.ई.सी. आयकर अधिनियम की धारा 54डग के अधीन नाबार्ड और एन.एच.ए.आई. के साथ पूंजी अभिलाभ कर छूट बाण्ड जारी करने की स्वीकृति देकर आर.ई.सी. के संसाधनों को बढ़ाना।

खाद्य अर्थव्यवस्था प्रबंधन

17. खाद्य अर्थव्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिये उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी नीति को मात्र कमियों के बजाय अधिशेषों पर कार्यवाई करने की ओर परिवर्तित करना होगा। खाद्यान्नों की उगाही की भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्था और राज्य प्रबंधित लोक वितरण प्रणाली से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जहां सब्सिडी, बजट अनुमानों में 8210 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में 12,125 करोड़ रुपए पर आ गई है, वहां संतुष्टिकरण स्तर नीचे आ गया है। अतः मैं संबंधित राज्यों में लोक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों की उगाही एवं वितरण दोनों में राज्य सरकारों को अधिक बड़ी भूमिका प्रदान करता हूँ। सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के बजाय राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह सब्सिडी वाली दरों पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये खाद्यान्नों की उगाही एवं उसका वितरण कर सकें। खाद्य सुरक्षा रिजर्व बनाने रखने के लिये और जो राज्य सरकारें अपनी ओर से यह कार्य उन्हें सौंपेंगी, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उगाही जारी रखेगा। इन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के ब्यौरे यथाशीघ्र राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जायेंगे।

18. अनेक निषेधात्मक नियंत्रणों एवं विनियमों के अस्तित्व से कृषि क्षेत्रक अभी भी बाधित है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये अधिनियम के अधीन अनिवार्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के नियंत्रण का प्रावधान है। राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक नियंत्रण आदेश जारी

किये हैं जो कुछ खाद्यां एवं कृषि उत्पादों की खुली आवाजाही को रोकते हैं। वर्तमान परिवर्तित स्थितियों में खाद्यान्नों एवं कृषि उत्पादों को लाने-ले जाने तथा भण्डारण पर अनुचित प्रतिबन्ध किसानों के लिये हतोत्साहन का कार्य कर रहा है।

19. अतः सरकार अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की पुनरीक्षा करने और खाद्यान्नों तथा कृषि उत्पादों को स्वतंत्र रूप से एक से दूसरे राज्यों में लाने-ले जाने और ऐसी वस्तुओं का स्टॉक रखने पर लगाये गये अनेक प्रतिबन्धों को हटाने का प्रस्ताव करती है। सरकार उक्त अधिनियम के अधीन घोषित अनिवार्य वस्तुओं की सूची की भी पुनरीक्षा करेगी और उनकी न्यूनतम आवश्यक संख्या रखेगी। मेरे सहयोगी माननीय खाद्य मंत्री, राज्य सरकारों से परामर्श के बाद इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

आधार सुविधायें

20. अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास आधार सुविधा-क्रियाकलापों में पर्याप्त निवेश पर निर्भर करता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा समुचित उपभोक्ता शुल्क लगाने का है जो निवेश को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने के लिये आवश्यक है। देश में आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिये 50 वर्षों में सरकारी क्षेत्रक में लोक-संसाधनों का निवेश किया गया है। इसका एक परिणाम यह रहा है कि उपभोक्ता शुल्क अनिवार्यतः राजनैतिक रूप से निर्धारणीय बन गये हैं। समय के साथ-साथ ऐसे न्यून उपभोक्ता शुल्कों में निहित "नान्-मेरिट सब्सिडीज" बढ़ते-बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक हो गई हैं जो सम्मिलित रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल राजकोषीय घाटे के बराबर हैं। अतः यह सभी स्तरों पर महसूस किये जा रहे राजकोषीय दबाव का एक बड़ा कारण बन गई हैं।

21. मैं समझता हूँ कि अब यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि संपूर्ण देश में इस पर अनिवार्य रूप से चर्चा करने की जरूरत है। चुनौती यह है कि उचित उपभोक्ता शुल्क इस तरह से लगाया जाय कि गरीबों को इससे संरक्षण मिले और जो इसका भुगतान कर सकते हैं वह करें, इस पर सहमति हो। तभी हम सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रकों में इन अनिवार्य सेवाओं के लिये निवेश बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। इसका एक प्रमुख उदाहरण विद्युत क्षेत्रक है।

विद्युत

22. आर्थिक विकास में तेजी लाने में विद्युत कितनी महत्वपूर्ण है इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य विद्युत बोर्डों की अंतर्निहित सब्सिडियों की कुल लागत इस वर्ष लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। क्रास-सब्सिडी और राज्यों की आर्थिक सहायता की गणना करने पर सम्मिलित रूप से सभी राज्य विद्युत बोर्डों का वास्तविक वाणिज्यिक नुकसान लगभग 24,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन आंकड़ों में परेषण एवं वितरण की आसाधारण भारी हानियां शामिल हैं।

23. यद्यपि इन सभी नुकसानों को राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य सरकारें वहन करती हैं, परन्तु मैं इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ कि यह एवं भारी राष्ट्रीय नुकसान है और यह केन्द्र सरकार के उपक्रमों को भी प्रभावित करता है। केन्द्र सरकार की जन सुविधाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों एवं अन्य की कुल देनदारी अब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। यदि यह संसाधन उपलब्ध होते तो देश को सभी के फायदे के लिये विद्युत क्षेत्र के विस्तार में पर्याप्त निवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बिजली की चोरी रोक्ने जानी चाहिए और लाभकारी शुल्क लगाये जाने चाहिए।

24. सुधार प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय सक्षमता बहाल करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प, 1992, तथा 1996 में तैयार किये गये न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम और फरवरी, 2000 के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सहमति के आधार पर राज्य सरकारों के साथ किये गये समझौता ज्ञापन में बनाये गये विशिष्ट उपलब्धि-मानदण्डों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार कार्यक्रमों में केन्द्र सरकार तेजी ला रही है। इन समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित विशिष्ट उपलब्धि-मानदण्ड शामिल हैं:-

- दिसम्बर, 2000 तक 100 प्रतिशत मीटर प्रणाली संस्थापन का एक समयबद्ध कार्यक्रम।
- सभी स्तरों पर ऊर्जा की लेखा परीक्षा।
- बिजली की चोरी में कमी और उसे समाप्त करने का एक विशिष्ट कार्यक्रम।
- एस. ई. आर. सी द्वारा शुल्क निर्धारण एवं उसका अनुपालन।
- वितरण कार्य का वाणिज्यीकरण और
- राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन।

इस कार्य के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रधान मन्त्री 3 मार्च, 2001 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करेंगे।

25. पांच राज्यों के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है, और अधिक राज्य सुधार प्रक्रिया को अपनायेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तदनुसार तीव्रीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के लिये योजना आबंटन 2000-01 में 1000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे सुधार करने वाले राज्यों को ए.पी.डी.पी. के अधीन प्रथमिकता दी जाएगी। वित्तीय सक्षमता बहाल करने की कुंजी वितरण सुधार है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि से सहायता को अन्य बातों के साथ साथ विद्युत सुधारों की उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाएगा। सुधार करने वाले राज्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) से रा. वि. बोर्डों को तरजीही आबंटन, उत्पादन एवं वितरण में सी.पी.एस.यू. द्वारा अतिरिक्त निवेश और विदेशी सहायता के तरजीही आबंटन के रूप में केन्द्र सरकार से सहायता भी प्राप्त करेंगे।

26. विद्युत क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया को तेज करने और इस क्षेत्रक के सभी विद्यमान केन्द्रीय कानूनों के एकीकरण के लिये मेरे सहयोगी विद्युत मंत्री इस सत्र के दौरान विद्युत विधेयक, 2001 प्रस्तुत करेंगे।

27. केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत सेवा हेतु योजना परियोजना इस वर्ष 9,194 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-02 में 10,030 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह विद्युत क्षेत्रकीय सुधारों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्रक के विद्युत निवेश को बढ़ाने की केन्द्र सरकार की बचनबद्धता को प्रदर्शित करता है।

सड़कें

28. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) इस देश के लिए एक नई सड़क कार्य-योजना को प्रदर्शित करता है। इसका अभूतपूर्व विस्तार एक बिल्कुल अलग किस्म की संयोजनता एवं गतिशीलता प्रदान करने की सरकार की उत्कट अभिलाषा का प्रतीक है। सड़क

विकास कार्यक्रम में तेजी लाने में सरकार की सफलता की कुंजी सड़क उपयोग के लिये उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाने की इसकी साहसिक नीति में निहित है। दिसम्बर 2003 तक पूरे किये जाने वाले चरण-1 के लिये संसाधन पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। 600 कि.मी. के पूरे किये गये प्रखण्डों के अलावा स्वर्ण घतुर्भुज के 1500 कि.मी. से अधिक मार्ग के लिये कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है। शेष हिस्से का कार्य इस वर्ष के मध्य तक किये जाने की आशा है।

29. उपकर ने ग्रामीण सड़कों, जिला सड़कों, राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देश में एकीकृत सड़क विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उपकर निधि से राज्य सड़कों के लिये राज्यों को 962 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस क्षेत्रक के लिए 2001-02 में कुल आयोजना परिव्यय 93 प्रतिशत बढ़ाकर 8727 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

दूर-संचार

30. सफलता का एक अन्य क्षेत्र दूर संचार क्षेत्रक है। प्राथमिक एवं सेन्सुअर सेवाओं, राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवाओं, इंटरनेट सेवा और दूर संचार सेवा विभाग के निगमीकरण से संबंधित 1999 की नई दूर संचार नीति में घोषित लगभग सभी नीतिगत उपायों को कार्यान्वित कर लिया गया है। सभी सेवा घटकों में प्रतियोगिता शुरू की जा रही है।

31. मार्च 2001 तक संपूर्ण टेलीफोन सघनता प्रति सौ पर 3.5 होने की आशा है जो केवल दो वर्ष पहले की तुलना में लगभग दुगुनी है। इसके अलावा नई प्रतियोगिताओं ने उपभोक्ताओं के लिये कीमतों में पहले ही कमी ला दी है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश में अब लगभग 800,000 (आठ लाख) एस.टी.डी./आई.एस.डी./स्थानीय बूथ हैं जो लगभग सभी उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और काफी रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं।

32. इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन की अनिवार्यताओं को समझते हुए सरकार दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रकों को एकीकृत तरीके से शामिल करने के लिये समविकासिता विधेयक (कन्वरजेंस बिल) पेश करने का प्रस्ताव करती है।

पत्तन

33. पत्तन क्षेत्रक के बारे में मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिये तैयार किये गये नीतिगत उपायों का भी सफलता के साथ कार्यान्वयन कर लिया गया है। बड़े भारतीय पत्तनों में समग्र क्षमता इस वर्ष 314 मिलियन टन और 2001-2002 के अन्त तक 376 मिलियन टन पर पहुंचने की आशा है और छोटे पत्तनों की क्षमता में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी। अब बड़े पत्तनों में पर्याप्त से अधिक क्षमता है। अब जलयानों को लंगर डालने (बर्थ) के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि पहले होता था।

34. इन्नोर पत्तन का पहले ही निगमीकरण कर दिया गया है और न्यू मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन अगला लक्ष्य है और अनुभव के आधार पर अन्य बड़े पत्तनों का भी निगमीकरण किया जा सकता है जिससे वह बाजार में संसाधन जुटा सकें। आर्थिक शुल्क स्तरों के निर्धारण से सफल निवेश संभव बनाया जा रहा है। बड़े पत्तनों के लिये टैरिफ (शुल्क) प्राधिकरण के गठन से इन शुल्कों को निरंतर पारदर्शी एवं निष्पक्ष आधार पर और आगे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार

35. पिछले कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय क्षेत्रक एवं पूंजी बाजारों में सुधारों को लाने में काफी प्रगति हुई है। मैं इस क्षेत्रक में सुधार जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

ऋण-बाजार

36. भारतीय शेयर बाजार एशिया में सबसे पुराना है। "सेबी" (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) के सृजन से शेयर बाजार की कार्यप्रणाली में काफी अधिक पारदर्शिता एवं स्वचालनता आ गई है। अब ऋण बाजार को विकसित एवं व्यापक बनाने की जरूरत है। यह लघु निवेशकों एवं सांस्थानिक निवेशकों के लिये समान रूप से काफी लाभदायक होगा। आधारभूत सुविधा क्षेत्रक को दीर्घकालिक निधियां जुटाने हेतु विशेषकर बीमा क्षेत्रक को खोलकर, समर्थ बनाया जाएगा।

37. सामान्य रूप से एक पारदर्शी एवं सक्रिय ऋण बाजार और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने के लिये मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के अधीन जिसका भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रवर्तक होगा, एक "क्लीयरिंग कारपोरेशन" की स्थापना की जाएगी और इसके जून, 2001 तक स्थापित होने की आशा है। यह विदेशी मुद्रा लेन-देनों के व्यवस्थापन में भी मददगार होगा।
- आदेश-संचालित स्क्रीन आधारित प्रणाली के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी।
- नीलामियों में पारदर्शी इलैक्ट्रॉनिक बोलियों और वास्तविक समय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 2001 तक एक इलैक्ट्रॉनिक बातचीत-शुदा लेन-देन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- निधियों के सरल एवं त्वरित अंतरण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगले वर्ष तक इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ई.एफ.टी.) एवं वास्तविक समय सकल व्यवस्थापन प्रणालियां (आर.टी.जी.एस.) स्थापित की जायेंगी।
- स्ट्रिप्स, जीरो कूपन बाण्ड, डीप-डिस्काउंट बाण्ड और इसी तरह के बाण्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं।
- पुराने लोक ऋण अधिनियम के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रतिभूतिकरण पर व्यापक कानून बनाया जाएगा।

38. इन क्रियाकलापों की मानिट्रिंग एवं कार्यान्वयन के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, शेयर बाजारों और वित्त मंत्रालय को शामिल करके एक छोटा ग्रुप स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि ऋण बाजार अगले वर्ष सक्रिय हो जाय।

बैंकिंग क्षेत्रक

39. पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्रक के सुधार चरणबद्ध तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। परन्तु बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की समस्या बनी हुई है। एन.पी.ए. की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:-

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2000-01 में 2 लाख खातों से 800 करोड़ एन.पी.ए. की वसूली की है।

- निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एन.पी.ए. 1993-94 में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में लगभग आधा अर्थात् 7.4 प्रतिशत है।
- 22 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) और 5 अपीली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है।
- वर्ष 2001-02 के दौरान 7 और डी.आर.टी. स्थापित किये जायेंगे।

40. मैं एक समुचित कानून लाने का भी प्रस्ताव करता हूँ जो चूक के मामलों में प्रतिभूतियों के पुरोबन्ध एवं प्रवर्तन में सहायक होगा ताकि संस्थायें अपनी बकाया धनराशियों की वसूली कर सकें।

41. बैंकिंग उद्योग में नई प्रतियोगिताओं के परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबन्धन सुदृढ़ करना आवश्यक है। मैं बैंक प्रबन्धनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। अपनी भर्ती कार्यनीति तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने में बैंक प्रबन्धनों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना भी अनिवार्य है। अतः मैं बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 31 जुलाई, 2001 या इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। भविष्य में सभी भर्तियां बैंकों द्वारा स्वयं की जायेंगी।

पूंजी लेखा उदारीकरण

42. लगभग 10 वर्ष पहले तक सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। उत्तरोत्तर यह नियंत्रण समाप्त हो गये हैं और वर्तमान खाता पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है। हमने पूंजी लेखा का भी कतिपय प्रयोजनों के लिए उदारीकरण कर दिया है। मैं पूंजी लेखे के उदारीकरण हेतु और कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ जो इस प्रकार है:-

- विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अब तीन वर्ष के मुनाफे की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से वार्षिक आधार पर 50 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती हैं।
- जिन कंपनियों ने ए.डी.आर./जी.डी.आर. जारी किये हैं अब वर्तमान 50% की सीमा के स्थान पर इन प्राप्तियों के 100% तक का विदेशी निवेश कर सकती हैं।
- अच्छे रिकार्ड वाली बड़ी धनराशियों का निवेश करने की इच्छुक कंपनियां अब विदेशी निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम ब्लाक-आवंटन प्राप्त कर सकती हैं।
- जिन भारतीय कंपनियों ने ए.डी.आर./जी.डी.आर. जारी किये हैं वह 100 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि तक या एक वर्ष में अपने निर्यातों की दस गुनी धनराशि के बराबर, जो भी अधिक हो, विदेशी कंपनियों के शेयर प्राप्त कर सकती हैं।
- ए.डी.आर./जी.डी.आर. को दोहरी प्रतिमोचनता प्रदान की जाएगी। परिवर्तित स्थानीय शेयरों को ए.डी.आर./जी.डी.आर. में पुनःपरिवर्तित किया जा सकता है और जहां कहीं लागू हो इस पर क्षेत्रकीय अधिकतम सीमा लगाई जा सकती है।
- अब भारतीय कंपनियों को ब्लाक शेयरधारिता के एवज में ए.डी.आर./जी.डी.आर. प्रायोजित करके विदेशी शेयर बाजारों में सूचीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारकों को प्रदान करनी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक अलग से इन मार्गनिर्देशों को जारी करेगा।

43. व्यावसायिक सेवायें प्रदान कर रही पंजीकृत भागीदारी वाली फर्मों और कंपनियों द्वारा निवेशों को अभी तक विदेशी निवेशों की अनुमति नहीं दी गई थी। अब यह प्रतिबन्ध हटाया जा रहा है। इसी तरह से भारतीय कर्मचारी जिन्हें विदेशी स्वागित्व वाली कंपनियों में ई.एस.ओ.पी. स्कीमों का लाभ मिलता है अब 5 वर्षों के ब्लाक के बजाय 20,000 अमरीकी डालर का वार्षिक विदेशी निवेश कर सकते हैं।

विदेशी निवेश

44. विदेशी निवेश से संबंधित उपबन्धों में उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है। मैं निम्नलिखित और उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :-

- विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24% तक पोर्टफोलियो निवेश मार्ग के अधीन किसी कंपनी में निवेश कर सकता है। इस सीमा को एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयर-धारकों की जनरल बाडी के अनुमोदन से 40% तक बढ़ाया जा सकता है। मैं इस सीमा को 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई) की अनुमति 100% तक प्रत्येक मामले के आधार पर दी जाती है परन्तु शर्त यह है कि उनकी धारिता का न्यूनतम 25% घरेलू बाजार में लगाया जाए। इस शर्त को हटाया जा रहा है बशर्ते विदेशी निवेशक न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करें। अब एन.बी.एफ.सी. में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की शर्त पर स्वतः मार्ग पर रखा गया है।

संरचनात्मक सुधार

45. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने के लिए हमें सुधार के कुछ कठिन क्षेत्रों को चुनना होगा जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

46. चार ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां मूल्य एवं मात्रा नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान है। यह क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम, उर्वरक, चीनी और औषधियां।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए.पी.एम.)

पेट्रोलियम

47. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सरकार ने नवम्बर, 1997 में मार्च, 2002 तक पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली हटाने के विस्तृत विवरण अधिसूचित किये थे। मैं इस निर्धारित समय के अनुपालन का प्रस्ताव करता हूँ। मार्च, 2002 तक ए.पी.एम. को विनियमन रहित करने के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मेरे सहयोगी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री इस संबंध में अलग से कार्य योजना निर्दिष्ट करेंगे।

उर्वरक

48. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने कुछ समय पहले विद्यमान प्रतिधारण मूल्य स्कीम (आर.पी.एस) को मध्यावधि में धीरे-धीरे समाप्त करने के उद्देश्य से उर्वरक मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाने की बात कही थी। सरकार ने अब 1 अप्रैल, 2006 तक यूरिया को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त रखने के चरणबद्ध कार्यक्रम के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ करके पहले चरण में निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे:-

- यूनिट विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य स्कीम के स्थान पर समूह रियायत स्कीम चलाई जाएगी। वर्तमान अधिकतम बिक्री मूल्य (एम.आर.पी.) जारी रखा जाएगा और प्रत्येक

समूह के लिए रियायत निर्दिष्ट की जाएगी ताकि यूनिट, निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य पर यूरिया बेच सकें।

- नेप्था/एफ.ए.ओ/एल.एस.एच.एस. के आधार पर यूरिया यूनिटों के लिए रियायत दर को इन आपूर्ति स्टाकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से सम्बद्ध किया जाएगा।

चीनी

49. सरकार चीनी को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के लिए बचनबद्ध है, परन्तु यह अन-उत्क्रमणीय होना चाहिए। सरकार ने आगामी वर्ष के अंदर चीनी में भावी सौदों/वायदा व्यापार को शुरू करने का निर्णय लिया है जो पूर्ण विनियंत्रण से पहले एक आवश्यक उपाय है। विशेष श्रेणी के राज्यों, पहाड़ी राज्यों, द्वीपसमूह क्षेत्रों और अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति राशन कार्ड धारकों को की जाएगी। ऐसी आपूर्ति चीनी के पूर्ण विनियंत्रण के बाद भी जारी रखी जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का खुदरा बिक्री मूल्य 1 मार्च, 2001 से 13.25 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है।

औषधि मूल्य नियंत्रण

50. हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उत्पाद पेटेंट प्रणाली के आगमन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने और चुर्नीतियों का सामना करने के लिए घरेलू औषधि एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता की जरूरत है। सरकार वर्तमान मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जहां वह अनुत्पादनकारी बन गई है, की कठिनाइयों को कम करने के उपायों पर विचार करती आ रही है। इस उद्देश्य के लिए हमने निर्णय लिया है कि मूल्य नियंत्रण समयावधि को पर्याप्त रूप से कम कर दिया जाएगा। फिर भी समाज के कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे मामलों में व्यापक रूप से दखल देने का अधिकार बनाये रखेगी जहां मूल्य व्यवहार असामान्य हो। तदनुसार फार्मास्यूटिकल्स नीति में परिवर्तन किये जा रहे हैं।

औद्योगिक पुनर्संरचना

51. सरकार ने कम्पनियों के पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण और/अथवा बंद करने के सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय विधि समिति का गठन किया है, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एस.आई.सी.ए को रद्द करने तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इन विधायी प्रस्तावों को मेरे सहयोगी विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा चालू सत्र के दौरान लाने का प्रस्ताव है।

श्रम बाजार

52. इन परिवर्तनों के साथ हमारे श्रम विधानों में सख्त विवादास्पद मामलों का समाधान करना भी आवश्यक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के कुछ मौजूदा उपबंधों ने औद्योगिक फर्मों के लिए किसी श्रम लोचशीलता का उपयोग करना लगभग असम्भव बना दिया है। सरकार अब इस विधान में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आश्वस्त है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय Vख में निर्दिष्ट है कि विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थापनों के नियोक्ता अस्थाई छंटनी, छंटनी तथा संस्थान को बंद करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। यह प्रस्ताव है कि ये उपबंध अब 100 कामगारों के बजाय 1000 तक के कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक-संस्थापनों पर लागू होंगे।

पृथक्करण क्षतिपूर्ति को सेवा पूर्ण करने की प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति की वृद्धि नियोक्ता को अस्थाई छंटनी, छंटनी का सहारा लेने और बार बार संस्थापन को बंद करने की प्रवृत्ति से रोकेंगी।

53. इसी प्रकार संविदा श्रमिक सम्बन्धी मौजूदा कानून कई सेवा गतिविधियों में रोजगार की वृद्धि को बाधित करता है। मौजूदा अधिनियम की धारा में कार्य/प्रक्रिया/प्रचालन में संविदा श्रम का निषेध परिकल्पित है, यदि उसमें निर्धारित कार्य की चिरस्थायी प्रकृति आदि जैसी शर्तें पूरी न की जाए। धारा 10 निषिद्ध कार्यों में नियोजित संविदा श्रमिकों को मूल नियोक्ता का प्रत्यक्ष कर्मचारी बनाने में समर्थ है। इस कठिनाई को दूर करने और साथ ही श्रमिकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि गतिविधियों के स्रोतों का बिना किसी प्रतिबन्ध के विस्तार करने तथा संविदा नियुक्तियों की पेशकश किए जाने सुविधाजनक बनाने के लिए एक संशोधन लाया जाए। इससे मुख्य और गौण गतिविधियों के बीच अन्तर नहीं होगा और विस्तारित स्रोत वाली गतिविधियों में लगे श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि की दृष्टि से संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इससे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए छंटनी मुआवजे के रूप में अंतिम आहरित वेतन पर आधारित अधिक मात्रा में मुआवजा भी मिल सकेगा।

54. इन उपायों से श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे नए सिरे से औद्योगिक विकास हो सकेगा और इसके साथ ही श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी। मेरे सहयोगी श्रम मंत्री औद्योगिक विवाद अधिनियम और संविदा श्रमिक अधिनियम में संशोधन करने के लिए इसी सत्र में एक उपयुक्त विधान लाएंगे।

आश्रय बीमा योजना

55. मैं अर्थव्यवस्था में चल रहे उदारीकरण के परिणामस्वरूप संगठित श्रम शक्ति पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव के बारे में सचेत हूँ। अतः मैं इस प्रकार प्रभावित श्रमिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 'आश्रय बीमा योजना' नामक सामूहिक बीमा की एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह पालिसी अपनी रोजी खोए हुए कामगारों के सम्बन्ध में एक वर्ष की समयावधि के लिए अन्तिम आहरित वार्षिक वेतन के 30 प्रतिशत भाग की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी। प्रारम्भ में प्रतिमाह 10 हजार रुपए का वेतन आहरण करने वाले सभी कर्मचारियों को इस पालिसी के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। सरकार के स्वामित्व की चार साधारण बीमा कम्पनियां इस पालिसी को 'हानि-लाभ रहित' आधार पर चलाएंगी और जून, 2001 के अन्त तक प्रस्तावित पालिसी की प्रीमियम दरों सहित पूर्ण ब्यौरे की घोषणा करेगी।

लघु उद्योग क्षेत्र

56. लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार की वचनबद्धता को बार-बार रेखांकित किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 30 अगस्त, 2000 को इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक पालिसी पैकेज की घोषणा की गयी थी।

57. इस क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, 1 सितम्बर, 2000 से छूट की सीमा को दोगुना करके 1 करोड़ कर दिया गया है।

58. अगस्त, 2000 की नई ऋण गारंटी योजना में चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है। संपार्श्विक के बिना ऋण की सीमा जो पहले 10 लाख रुपए पर निर्धारित की गयी थी, उसे इस योजना के अधीन बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 7 बैंकों का ऋण गारंटी निधि न्यास के साथ, जिसे योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित किया गया है, पहले ही करार हो चुका है। प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सम्बन्ध पूंजी सस्मिडी योजना को 12 प्रतिशत पूंजीगत सस्मिडी के साथ अक्टूबर, 2000 में प्रारम्भ किया गया है। आशा है कि

इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध होंगे।

59. हमारे लघु उद्यमियों ने राष्ट्रीय निर्यात में 35 प्रतिशत से अधिक का योगदान करके अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता साबित कर दी है। कुछ अति महत्वपूर्ण निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में और नए निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अब चर्म वस्तुओं, जूतों और खिलौनों से सम्बन्धित 14 अन्य मदों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव है।

वस्त्रोद्योग

60. सरकार ने हाल ही में एक नई वस्त्र नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य उद्योग को गहन और मुक्त विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की नई चुनौतियों के लिए तैयार करना है। मुझे एक टेक्सटाइल पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी है जिसमें निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं :-

- एकीकृत परिधान पार्क (इंटीग्रेटेड एफेरल पार्क) की स्थापना करने की एक स्कीम शुरू की जा रही है। इससे अनारक्षित रेडीमेड गारमेंट उद्योग सर्वोत्तम आधारभूत ढांचायुक्त आधुनिक इकाइयां स्थापित कर सकेगा। वर्ष 2001-02 के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
- इस प्रयोजन हेतु एक सुदृढ़ और आधुनिक बुनकरी क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 50,000 नये शटल रहित करघों और 2.5 लाख सादे करघों को स्वचालित करघों में बदल कर आधुनिकीकरण का कार्य 2004 तक होने की आशा है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस) से निधियां मुहैया कराई जाएंगी। टी.यू.एफ.एस के अधीन बजट प्रावधान को इस वर्ष 50 करोड़ रुपए के आवंटन से बढ़ाकर अगले वर्ष 200 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन को जारी रखा जा रहा है और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु बजट प्रावधान पिछले वर्ष 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- कपड़ा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 2000-01 में 457 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-02 में 650 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- प्रस्तावित राजकोषीय परिवर्तनों का ब्यौरा मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में दूंगा।

मानव-विकास

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

61. सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन को 4920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5780 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें एचआईवी/एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए 180 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

62. जड़ी-बूटियों में अब समूचे विश्व की रुचि बढ़ रही है क्योंकि लोग इलाज की ऐसी सरल पद्धतियों की ओर रुख कर रहे हैं जिनके प्रतिकूल प्रभाव (साइड इफेक्ट्स) न हों। हम पेटेन्टों की मंजूरी को रोकने के लिए जन-मानस में पहले से मौजूद जानकारी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए एक पारम्परिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं। हम राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेशियों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई

स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को भी फार्मास्यूटिकल उद्योग की तरह लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा

63. बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम-सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एक मिशन रूप में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को आठ वर्ष की अच्छी बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें मुख्य जोर सामुदायिक स्वामित्व वंचित तबकों और बालिकाओं की अच्छी शिक्षा और शिक्षा के वैकल्पिक तरीके पर होगा। बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यमान स्कीमों को नौवीं योजना के बाद इस योजना में मिला दिया जाएगा और अगले वर्ष मार्च तक देश के सभी जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा।

64. हम प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने के प्रति कटिबद्ध हैं। इस प्रयोजन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन स्थापित एक कार्य दल ने शिक्षा के इस क्षेत्र का उन्नयन और विस्तार करने के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं, रुड़की इंजीनियरिंग कालेज का आई.आई.टी. के रूप में उन्नयन किया जाएगा और आई.आई.टी. गुवाहाटी को और अधिक मात्रा में निधियां प्रदान की जा रही हैं जिससे कि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। आई आई टी के आधार का विस्तार किया जाएगा, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को सुदृढ़ किया जा रहा है और सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारी से नए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जाएगा, विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई स्कीम शुरू की जा रही है और विद्यालय से महाविद्यालय स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें की जा रही हैं।

65. पिछले वर्ष मैंने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाओं को की गई अदायगियों पर शत-प्रतिशत आयकर छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। मैं यही छूट इंजीनियरिंग संस्थाओं को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण

66. अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं गरीबी का अनुभव किया है और उच्चतर शिक्षा अर्जन में मैंने दिक्कतों का सामना किया है। अतः मेरा मानना है कि देश के किसी भी सुयोग्य छात्र को धन की कमी की वजह से उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) ने एक व्यापक शैक्षणिक ऋण स्कीम तैयार की है जिसके दायरे में भारत तथा विदेशों में सभी पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। इस स्कीम के तहत भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए और विदेशों में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए के ऋण उपलब्ध होंगे। 4 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी जमानती या मारजिन की शर्त नहीं रखी जाएगी और इसका ब्याज सर्वोच्च उधार दर (पीएलआर) से अधिक नहीं होगा। 4 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दर पीएलआर जमा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस ऋण की वापसी-अदायगी 5 से 7 वर्ष की अवधि में की जाएगी और इसमें छूट की अवधि का प्रावधान होगा। मुझे आशा है कि इस स्कीम से जरूरतमंद बच्चे भारत में और उससे बाहर उच्च व तकनीकी अध्ययन कर सकेंगे।

महिलाएं

67. वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

इस बीच मेरा प्रस्ताव है कि :-

- गरीब परिसंपत्तिविहीन महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष को सुदृढ़ किया जाए।
- महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 650 विकास खंडों में महिलाओं की अधिकारिता की एक एकीकृत स्कीम शुरू की जाय।
- दुरुह परिस्थितियों में रह रही महिलाओं जैसे वृन्दावन, काशी और अन्य स्थानों की विधवाओं, अकिंचन महिलाओं और अन्य वंचित महिला समूहों के लिए एक नई स्कीम शुरू की जाए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

68. अनुसूचित जनजातीय आबादी के और अधिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ की गई है। जनजाति कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की स्कीमों हेतु आवंटन इस वर्ष 786 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 986 करोड़ रुपये किया गया है।

69. इसी तरह अनुसूचित जातियों की आबादी के कल्याण और उत्थान की स्कीमों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आवंटन को इस वर्ष 709 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष में 790 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा

70. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले बजट में मैंने समाज के सबसे गरीब तबकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु 'जनश्री बीमा योजना' नामक एक नई सामूहिक बीमा योजना की घोषणा की थी। इस स्कीम का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त, 2000 को उद्घाटन किया गया और इसका व्यापक स्वागत हुआ है। अब तक 332 स्कीमों को मंजूरी दी गई है और 99,750 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

71. मेरा विश्वास है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मुसीबतों को कम से कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार मेरा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दो और स्कीमों शुरू करने का प्रस्ताव है:

- (i) भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक विशेष स्कीम खंतिहर मजदूर बीमा योजना, जिसके तहत लाभार्थी को जनश्री बीमा योजना के अधीन उपलब्ध की तरह बीमा कवर के लाभ और उसके 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100 रु. प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी। उन लाभार्थियों के मामले में जो युवावस्था में ही इस स्कीम में शामिल होंगे, प्रति दस वर्ष की समाप्ति पर कुछ आवधिक भुगतान भी परिकल्पित है। लाभार्थी को प्रीमियम के रूप में एक अल्प अंशदान करना होगा।
- (ii) एक शिक्षा सहयोग योजना, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों को 100 रुपये प्रतिमाह का शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा ताकि वे नौवीं से बारहवीं कक्षा के अपने अध्ययन के दौरान शिक्षा के खर्चों को वहन कर सकें जिससे कि कोई जरूरतमन्द छात्र धन के अभाव में अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर से वंचित न रह जाय। यह जनश्री बीमा योजना के अभिदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।

इन स्कीमों का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

72. इस बीच, मंरे पास कम मजदूरी पाने वाले कामगारों के लिए खुशखबरी है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन कवरेज के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 6.500 रुपए कर दी गई है। कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देने के लिए मैं पेंशन निधि में कर्मचारियों की मासिक मजदूरी के 1.16 प्रतिशत के सरकारी अंशदान की अधिकतम सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस मद पर अतिरिक्त व्यय 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।

73. इस समय क्षेत्र में जहां विभिन्न पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी स्कीमों के फायदे मिलते हैं, वही असंगठित क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त नहीं है। मैंने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण से इन सभी मुद्दों की जांच करने और 1 अक्टूबर, 2001 तक पेंशन सुधारों का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है।

पत्रकार कल्याण निधि

74. पत्रकारों को आतंकवाद और अन्य हिंसा की घटनाओं की खबरें पहुंचाने के लिए अधिकाधिक जोखिम उठाने पड़ते हैं। उनकी सेवाओं और बलिदानों की मान्यतास्वरूप और उनसे बेहतर बर्ताव की आशा में, मेरा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए के अंशदान से एक पत्रकार कल्याण निधि गठित करने का प्रस्ताव है। मेरी सहयोगी सूचना व प्रसारण मंत्री इस स्कीम के ब्यौरे की घोषणा करेंगी।

मनोरंजन

75. हमारा मनोरंजन उद्योग विशेष रूप से फिल्म उद्योग हमारे लाखों लोगों को जो अन्यथा कठोर तथा निर्दय विश्व में रह रहे हैं, अत्यावश्यक मनोरंजन की न केवल व्यवस्था करता है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी उभरा है और इसकी भविष्य में उज्ज्वल सम्भावनाएं हैं। दो वर्ष पहले, मैंने इस उद्योग को वही कर छूट प्रदान की थी जो पण्य-निर्यातों के लिये उपलब्ध थी। कुछ माह पहले सरकार ने आईडीबीआई अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग का एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में घोषित कर दिया गया है। बैंक ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये मार्ग-निर्देश अंतिम रूप से तैयार कर रहे हैं जो बैंक-ग्राह्य हैं। मुझे आशा है कि फिल्म उद्योग अपने प्रचालनों में और अधिक पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता लाने के लिए इन उपायों का पूरा लाभ उठाएगा और ऐसा कोई कार्य चुपके-चुपके और निश्चित तौर पर चोरी-चोरी नहीं करेगा।

राजकोषीय सुदृढ़ता

76 जैसा कि मैंने पहले कहा है अर्थव्यवस्था जिस अत्यधिक गम्भीर समस्या का सामना कर रही है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति है। इन दोनों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के आसपास है। मुझे अक्सर राजकोषीय रूढ़िवादी के रूप में समझा जाता है। कुछ लोग मुझे राजकोषीय चरमपंथी कहने की सीमा तक पहुंच गए हैं। मैं राजकोषीय घाटे के प्रति क्यों इतना चिन्तित हूँ, मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दें। वजट अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियां लगभग 281,000 करोड़ रुपए हैं। इस राशि में से, केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्यों का हिस्सा 72,000 करोड़ रुपए है। इसलिए केन्द्र सरकार के पास 209,000 करोड़ रुपए शेष रहते हैं। व्यय के मामले में 101,000 करोड़ रुपए ब्याज पर, 59,000 करोड़ रुपए रक्षा पर, 23,000 करोड़ रुपए बड़ी सब्सिडियों पर और 16,000 करोड़ रुपए पेंशनों पर खर्च किए जाते हैं। अन्य सभी सरकारी

व्यय की निवल राशि कुल 123,000 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि केवल 12,000 करोड़ रुपए शेष बचे हैं। इसलिए काम चलाने के लिए चालू वर्ष में मुझे 111,000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। सर्वाधिक चिन्ताजनक पहलू यह है कि मेरे उधारों की राशि का 70 प्रतिशत से अधिक भाग अर्थात् 77,000 करोड़ रुपए अनुत्पादक राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए था। यह अगले वर्ष ब्याज के रूप में मेरा भार बढ़ाएगा तथा अधिक से अधिक उधार लेने तथा ऋण जाल में फंसने को अंततः मुझे मजबूर करेगा। मैं हमारे फिजूलखर्ची द्वारा भावी पीढ़ी पर डाले जा रहे बोझ के प्रति अत्यधिक चिन्तित हूँ। मैं इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता।

77. मेरे पिछले बजट भाषणों में दिए गए अपने आश्वासनों के अनुरूप मैंने गत वर्ष व्यय सुधार आयोग की नियुक्ति की थी और इस सदन में पिछले सत्र में राजकोषीय दायित्व विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक में राजकोषीय घाटे को घटाकर 2 प्रतिशत पर लाने और आगामी पांच वर्षों में राजस्व घाटे को पूर्णतया समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

78. विशेष रूप से आयोजना-भिन्न व्यय में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने हेतु कई उपाय पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए हैं। मैंने इस वर्ष आयोजना-भिन्न व्यय में किसी भी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी है, परिणामस्वरूप, कई वर्षों में पहली बार बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है और यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 5.1 प्रतिशत पर है। 3.6% का राजस्व घाटा लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है।

व्यय प्रबंधन

79. मेरी मंशा केन्द्रीय सरकार के व्यय के संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और आयोजना व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते समय आयोजना-भिन्न राजस्व में और अधिक उत्साह से मितव्ययिता बरतते हुए आगे बढ़ने की है। इसके लिए, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं के उपभोक्ता प्रभागों को इन सेवाओं की वर्धित लागत को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। इस वृद्धि का एक हिस्सा इन सेवाओं के अनुरक्षण तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसी प्रकार, डाक दरों को, बढ़ते हुए डाक घाटे को नियंत्रित करने के लिए मामूली रूप से संशोधित किया जाएगा।
- भर्ती की सभी अपेक्षाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाएगी कि नई भर्ती कुल सिविलियन स्टाफ की संख्या के 1 प्रतिशत तक सीमित रहे। चूंकि स्टाफ का लगभग 3 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है, इसलिए इससे प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की जनशक्ति में कमी आएगी और इस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पांच वर्षों में 10 प्रतिशत स्टाफ की कटौती करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।
- कार्मिक विभाग के अन्तर्गत अधिशेष पूल को आधिक्य स्टाफ की पुनः तैनाती और पुनः प्रशिक्षण देने हेतु प्रभावी और सुसज्जित बनाया जाएगा। सरप्लस पूल के कर्मचारियों को आकर्षक स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का पैकेज भी दिया जाएगा।
- सरकारी आवास पर मानक लाइसेंस शुल्क (किराया) को 1 अप्रैल, 2001 से समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत, समूह 'ख' के लिए 25 प्रतिशत और स्टाफ के अन्य संवर्गों हेतु 15 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत को चार वर्ष के ब्लाक अवधि के शेष भाग हेतु 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा लेकिन इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जो सेवानिवृत्ति से पहले अन्तिम अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं।
- सरकारी गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को कार्यकुशलता को बढ़ावा देने हेतु विस्तारित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, वेतन और लेखा, पासपोर्ट, आयकर, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों को 31 मार्च, 2002 तक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कम्पनियों से भी कहा जा रहा है कि वे इस अवधि के भीतर अपने कार्यकलापों में पूर्णतः कम्प्यूटर का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दें।

80. पिछले वर्ष गठित व्यय सुधार आयोग ने 7 मंत्रालयों और विभागों का आकार छोटा करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें आर्थिक कार्य विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, सरकारी उद्यम विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय, और आपूर्ति विभाग शामिल हैं। आयोग की अन्य विभागों से संबद्ध रिपोर्टें भी आगामी छह माह के भीतर प्राप्त हो जाएंगी। इन सिफारिशों को 31 जुलाई, 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा और पहचान किए गए अधिशेष स्टाफ को सरप्लस पूल में स्थानान्तरित किया जाएगा।

81. एक कहावत है कि 'पहले अपने, पीछे पराए'। मेरा विश्वास है कि मितव्ययिता भी अपने घर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं आर्थिक कार्य विभाग के तीन सचिव/विशेष सचिव स्तर के और दो संयुक्त सचिव स्तर के पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसे चरणबद्ध तरीके से 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यय सुधार आयोग द्वारा संस्तुत 31 पदों की तुलना में निदेशक और उससे नीचे के अन्य 44 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। मुद्रा और सिक्का ढलाई प्रभाग में 1675 पदों को समाप्त किया जा रहा है। इस प्रभाग की पुनर्संरचना की जाएगी तथा उसे निगम का स्वरूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत संगठन की स्टाफ संख्या को 1191 से घटाकर लगभग 25 करके छोटा किया जाएगा। मैंने व्यय सुधार आयोग से कहा है कि वह राजस्व तथा व्यय विभाग के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें प्रदान करे। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में संस्थापनों के आकार को छोटा करने की प्रक्रिया तेज होगी।

82. योजना आयोग ने दसवीं योजना को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संसाधनों की गम्भीर अड़चनों को देखते हुए सरकार के व्यय की गुणवत्ता में सुधार अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सभी ऐसी योजनाएं जो स्वरूप में एकसमान हैं, उन्हें दोहराव को समाप्त करने के लिए एकरूप कर दिया जाएगा। केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं जो राज्यों को अन्तरित हो सकती हैं, की पहचान की जाएगी। संसाधनों में निवेश को निष्पादन से जोड़ा जाएगा। योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी किए जाएंगे। विकेंद्रित नियोजन को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा।

पेंशन सुधार

83. केन्द्र सरकार की पेंशन देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनियंत्रणीय अनुपातों तक पहुंच गयी हैं। ये 1993-94 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2000-2001 में

1 प्रतिशत हो गयी, जैसी कि व्यवस्था है कि जो कर्मचारी केन्द्र सरकार की सेवाओं में 1 अक्टूबर, 2001 के बाद प्रवेश करते हैं, वे परिभाषित अंशदानों के आधार पर नवीन पेंशन कार्यक्रम के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। मौजूदा पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु तथा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आगामी कदमों की रूपरेखा उपलब्ध कराने हेतु मैं एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह के गठन का प्रस्ताव करता हूँ, जो अपने सिफारिशें 3 महीने के भीतर देगा।

84. मैंने व्यय बजट में ऋण शोधन बोझ के बढ़ते हुए हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, जो बढ़ते हुए सरकारी कर्ज और मौजूदा उच्च वास्तविक ब्याज दरों द्वारा तीव्र होने की वजह से है। व्यय बजट में अर्थव्यवस्था में अधिकांश ब्याज दरें अब बाजार निर्धारित हैं। परंतु उनका नीचे आना संविदात्मक बचत क्षेत्र अर्थात् भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं को नियंत्रित करने वाली प्रशासित ब्याज दरों में अन्तर्निहित सख्ती द्वारा बाधित है। मैंने बहुत सावधानीपूर्वक इस मुद्दे की जांच की है। मैंने पाया है कि इन सभी योजनाओं में प्रदान की गई ब्याज दरें वर्ष 1980 और 1998 के बीच कभी भी 3 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से अधिक नहीं हुई हैं। तबसे, यह अंतर बढ़कर 6 से 8 प्रतिशत हो गया है। न केवल केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों पर अवहनीय बोझ डालने वाली ऐसी उच्च वास्तविक ब्याज दरें ही बल्कि पूंजी की परिणामी उच्च लागत भी पूर्ण रूप से आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतएव मैं इन प्रशासित दरों को 1 मार्च, 2001 से कम करके 1.5 प्रतिशत कर रहा हूँ। इन योजनाओं के लिए सरकारी गारंटी और कर-प्रोत्साहन जारी रहेंगे। भविष्य के लिए मैं इन दरों के निर्धारण के लिए एक बेहतर प्रणाली का पता लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस मुद्दे पर सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

85. लघु बचत जमाशायियों पर ब्याज दरों में कमी के लाभ पूर्ण रूप से राज्यों को प्राप्त होंगे। यह लघु बचतों से उनकी उधार लेने की लागत 100 से 150 आधार बिंदु तक कम कर देंगे। इसके अतिरिक्त, मैं राज्य आयोजनाओं को केंद्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज को भी 50 आधार बिंदु कम कर रहा हूँ। राज्य सरकारों द्वारा केंद्र में भविष्य निधि की घटी हुई ब्याज दरों के साथ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दरों को समान करना राज्य सरकारों का व्याज भार और कम कर देगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र के सकल कर संग्रहण में पूर्वानुमानित वृद्धि के कारण राज्यों को केंद्रीय करों की सुपुर्दगी की राशि चालू वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 में लगभग 9000 करोड़ रुपए बढ़ जाने का अनुमान है। ये सभी उपाय राज्यों के ऋण भार को कम करने में सहायता करेंगे और उनकी राजकोषीय स्थिति में सुधार लाएंगे।

राज्य के राजकोषीय सुधार

86. केन्द्र में राजकोषीय समेकन से हमारा प्रयास राज्यों के साथ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उनकी वित्तीय दशा में सुधार करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। राज्यों को अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यान्वित करने के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 10,607 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई है। ये सुधार अनिवार्यतः राज्यों के अपने कार्यक्रम होंगे और प्रत्येक राज्य को अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्याप्त छूट दी गई है। राजकोषीय वर्ष 2001-2002 में मैंने इस प्रोत्साहन निधि को 4243 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

सरकारी क्षेत्र का पुनर्गठन और निजीकरण

87. हमारे सरकारी क्षेत्र ने आर्थिक कार्यकलाप के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना विस्तार किया है। कई प्रकार से, इसने राष्ट्र की अच्छी सेवा की है; दक्षता का चहुंमुखी विकास हुआ है

और एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार निर्मित हुआ है। इन उद्यमों को नए वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और प्रगति करने के लिए अब सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने स्पष्ट रूप से इस संबंध में सरकार की नीति परिभाषित की थी।

88. 'सेल' और 'एचएमटी' सहित सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों की वित्तीय और व्यापार पुनर्गठन योजना वर्ष के दौरान अनुमोदित की गई थी। वर्ष 1998 से व्यवहार्य और संभावित रूप से व्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के 23 उपक्रमों को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय पुनर्गठन सहायता प्रदान की गई है। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 8 अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का भी निर्णय किया है। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की विभिन्न मिलों का पुनरुद्धार और बंद करने के लिए भी उपायों का पैकेज अनुमोदित किया गया है।

89. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की कार्यविधि भी अब काफी सरल और कारगर बना दी गई है। निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए विनिवेश विभाग का गठन किया गया है। सरकार की आय को अधिकतम करने के लिए हमारा दृष्टिकोण शेयरों की अल्प मात्रा के विनिवेश से महत्वपूर्ण निवेशकों के शेयरों के ब्लाक की महत्वपूर्ण बिक्री करने की ओर अंतरित हो गया है। सरकार 27 कंपनियों का निजीकरण अनुमोदित कर चुकी है, जिनमें विनिवेश की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने का अनुमान है। इन कंपनियों में अन्यो के अलावा विदेश संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया और मारुति उद्योग लिमिटेड शामिल है।

90. इन कई कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया के उन्नत चरण को देखते हुए, मैं अगले वर्ष के दौरान विनिवेश से 12000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का श्रेय लेने के लिए प्रोत्साहित हुआ हूँ। इसमें से 7000 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता, कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने और त्रण-भार को कम करने में किया जाएगा। प्राथमिक तौर पर सामाजिक और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में योजना के लिए अतिरिक्त बजट सहायता प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग किया जाएगा। योजना के लिए यह अतिरिक्त आवंटन पूर्वानुमानित प्राप्तियों की वसूली पर आधारित होगा। योजना आयोग के परामर्श से मैं वर्ष के दौरान क्षेत्रकीय आवंटन प्रस्ताव लाऊंगा।

गुजरात का भूकम्प

91. गुजरात में भूकम्प जन-जीवन की क्षति और संपत्ति की हानि के रूप में एक भयावह और अभूतपूर्व दुखद घटना रही है। यद्यपि, मैं विश्वास करता हूँ कि गुजरात के लोगों की अन्तर्निहित सहिष्णुता और उद्यमशीलता की भावना आर्थिक कार्यकलापों को शीघ्र ही बहाल कर देगी फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे पास अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग से विचलित हुए बिना ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का पूरी तरह सामना करने की क्षमता है।

92. इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार निम्नलिखित सहायता प्रदान कर रही है:

- राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से तत्काल 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे।
- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक संचित निधि से गठित राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को वैयक्तिक आयकर और निगम कर पर 2 प्रतिशत अधिभार लगाकर बढ़ाया जा रहा है।

- सड़कों, पुलों, विद्युत संस्थापनाओं, स्कूल की इमारतों, जन सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाएगी।
- 800 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया। संयुक्त दल गुजरात का भ्रमण कर चुका है और पर्याप्त अतिरिक्त निधियों पर बातचीत करना अनुमानित है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्र में उधारकर्ताओं के लिए वसूलियों को रोक देने और उदार शर्तों पर नए ऋणों के विस्तार के लिए बैंकों से विशेष व्यवस्था करने का अनुदेश दिया है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक और 'हुडको' ने आवास निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां अलग रखी हैं। मैं दोनों संस्थाओं के बीच 2000 करोड़ रुपये तक के कर मुक्त बाण्डों का विशेष कोटा आवंटित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।
- उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद की गयी कार्रवाई की भांति, इंदिरा आवास योजना में 'हुडको' और राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी।
- गुजरात सरकार को कर-मुक्त भूकम्प राहत बांड जारी करके निधियां जुटाने योग्य बनाया जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अनिवासी भारतीयों सहित व्यक्तियों और अन्यो को रुपये में अभिदान के लिए खुला होगा।
- राहत के लिए अभिप्रेत सभी सामग्रियों को उत्पाद और सीमा शुल्कों से छूट दी गई है; प्रत्यक्ष कर निर्धारितियों के अपनी विवरणियां दाखिल करने के लिए समय में बढ़ोत्तरी की गई है।

93. इस भयानक प्राकृतिक आपदा ने राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी संस्थागत व्यवस्था करने की आवश्यकता भी प्रदर्शित की है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति इस प्रयोजन के लिए प्रभावी दीर्घावधिक कार्यनीति बनाने के लिए सिफारिश करेगी।

बजट अनुमान

वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान

94. हम विनिवेश कार्यक्रम के धीमेपन, प्राकृतिक आपदाओं और पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं को राहत देने के कारण सरकारी वित्त पर दबाव पड़ने के बावजूद राजकोषीय घाटे के बजट लक्ष्य को बनाये रखने में सफल हुए हैं। चालू राजकोषीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 2965 करोड़ रुपये की मामूली कमी है।

95. केन्द्र का निवल कर-राज्य 1,46,209 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 1,44,403 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 1806 करोड़ रुपये की कमी प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यतः सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क के कम संग्रहण के कारण है, जिसमें पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए उसमें कमी की गई थी। कर-भिन्न राजस्व का अनुमान 57,464 करोड़ रुपये के अनुमानित स्तर से 4299 करोड़

रुपए अधिक होकर 61,763 करोड़ रुपया अनुमानित है। परन्तु, विनिवेश प्राप्ति 10,000 करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य की तुलना में कम होकर 2500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

96. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य के अनुरूप अर्थात् 5.1% होने की आशा है।

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान

97. वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 3,75,223 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें से आयोजना व्यय 100,100 करोड़ रुपए और आयोजना-भिन्न व्यय 2,75,123 करोड़ रुपए है।

आयोजना व्यय

98. केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट सहायता 100,100 करोड़ रुपए रखी गई है, जो 2000-2001 के संशोधित अनुमानों से 13,862 करोड़ रुपए अधिक है। यह 16 प्रतिशत की वृद्धि है। केन्द्रीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 48,269 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-2002 में 59,456 करोड़ रुपए की जा रही है। वर्ष 2001-2002 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता भी 2001-2002 के संशोधित अनुमान में, 37,969 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,644 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

आयोजना-भिन्न व्यय

99. वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 2,49,284 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 में आयोजना-भिन्न व्यय 2,75,123 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज संदाय (11,633 करोड़ रुपए), रक्षा (7,539 करोड़ रुपए) और राज्य सरकारों को अनुदान (2,221 करोड़ रुपए) के कारण है।

100. अधिक विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए मैं बजट पत्रों के साथ इस वर्ष '1999-2000 और 2000-2001 में की गई बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन' पर एक नई रिपोर्ट भी संलग्न कर रहा हूँ।

भाग ख

महोदय,

101. मैं अब अपने कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूँ। पहले अप्रत्यक्ष करों को लें।

102. अपने पहले के बजटों में मैंने अपने राजस्व प्रस्तावों को तैयार करने में प्रयत्नों का निरन्तरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस दिशा में जो सिद्धांत और पथ प्रदर्शक रहे हैं, वे हैं - राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता, कर व्यवस्था का सरलीकरण और योजितकीकरण और ईमानदार करदाता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं करवंचक के लिए निवारक उपायों के जरिए कारगर कर-अनुपालन। मैंने सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क दोनों में अनेक दरों में समता की है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया है और कर अनुपालन में सुधार लाने के उपाय शुरू किए हैं। मैंने खास मामलों में उत्पाद और सीमा-शुल्क छूटें प्रदान करने की अपनी विवेकाधीन शक्तियों का त्याग किया है और इस प्रकार सरकार के लिए राजस्व के कई करोड़ रुपए बचाए हैं। कर वंचकों के विरुद्ध दंडों की नीति भी भेदभाव रहित बनाई गई है। मेरे इन सभी उपायों का उद्देश्य एक ऐसे तंत्र को समाप्त करना रहा है जिसे समूह या लॉबियां प्रभावित कर सकती हैं। इस वर्ष मेरा प्रयास है कि इस प्रक्रिया को इसकी न्यायोचित परिणति पर पहुंचाया जाए।

103. मैंने अपने पिछले बजट में केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) की दर के रूप में 16% की दर लागू की थी। मैंने विशेष उत्पाद शुल्क की दरों में भी युक्तिसंगतता लाकर इन्हें तीन अर्थात् 8%, 16% और 24% कर दिया था। सेनवेट की एकल दर का अब यथामूल्य शुल्कों से कुल उत्पाद-शुल्क राजस्व में लगभग 68% का अंशदान है।

104. मेरा अब विशेष उत्पाद शुल्क की तीन दरों को कम करके 16% की एक दर लागू करने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप, मैं निम्नलिखित मदों पर 8% विशेष उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ:

(1) ग्लेज्ड टाइलें

- (2) गद्दे (मैट्रेस) और शैय्या का सामान
- (3) कार्पेट और फ्लोर कवरिंग
- (4) पेन्टेड कैन्वास, स्टूडियो बैक कलाथ आदि
- (5) लिनोलियम और टेक्सटाइल वॉल कवरिंग
- (6) स्कूटर और मोटरसाइकिल और
- (7) टैक्सियां।

इन मदों पर अब केवल 16% की दर पर सेनवेट प्रभार्य होगा।

105. सफेद सीमेंट और अन्य विशेष सीमेंट, याट और नौका विहार वाली नावों, निजी इस्तेमाल के लिए हथियार एवं गोला बारूद और लोमघर्म (फर स्किन) की बनी वस्तुओं पर 16% का विशेष उत्पाद-शुल्क और कुल 32% शुल्क लगेगा।

106. वातित सॉफ्ट ड्रिंक, वेंडिंग मशीनों को आपूर्ति किए गए सॉफ्ट ड्रिंकों के सान्द्र और मोटरकारों पर विशेष उत्पाद-शुल्क को कम करके 16% किया जाएगा, इस प्रकार 24% विशेष उत्पाद-शुल्क की दर को समाप्त किया जाएगा। इन मदों पर भी अब 32% का कुल शुल्क लगेगा। जिन उत्पादों पर पहले से 32% की यह दर लागू है उनके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

107. कुछेक ऐसी मदें हैं जिन पर इस समय आधी दर अर्थात् 8% पर सेनवेट लगता है। इन सभी मदों पर अब से 16% की सामान्य दर प्रभार्य होगी सिवाय सिलाई के धागे सहित सूती धागा, एल.पी.जी., कैरोसीन और 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजिन जिन्हें मैं व्यापक जनहित में फिलहाल 8% पर छोड़ रहा हूं।

108. इन यौक्तिकीकरण उपायों के बाद यथामूल्य शुल्कों के संबंध में राजस्व का लगभग 80% 16% की एकल दर से और लगभग 17% 32% की सम्मिलित दर से आएगा।

109. भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परन्तु समुचित भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में इनका अधिकांश भाग बर्बाद चला जाता है। शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों के कारोबार में लगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष मदद की आवश्यकता है। अतः मैं फलों और सब्जियों से तैयार वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें आम इस्तेमाल के बहुत सारे उत्पाद जैसे अचार, सॉस, केचप और जूस आदि शामिल होंगे। बेहतर भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए मेरे द्वारा दी गई सहायता के साथ-साथ इन सुविधा से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में यह सहायक साबित होगा।

110. ग्यारहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में धन जुटाने के लिए एक विशेष उगाही शुल्क की सिफारिश की है। एक तदर्थ उपाय के तौर पर चालू वर्ष में कॉरपोरेट करों पर एक विशेष अधिभार के जरिए इसकी व्यवस्था की गई थी। मैं कई ऐसे उत्पादों, जिनके इस्तेमाल को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, पर उत्पाद-शुल्क के एक विशेष अधिभार के जरिए नियमित रूप से इसके निधिपोषण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सिगरेट पर 15% अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूं। बीड़ी पर शुल्क बढ़कर 6 रुपए से 7 रुपए प्रति हजार बीड़ी हो जाएगा। पान मसाला पर कुल शुल्क 55%/60% हो जाएगा। विविध तम्बाकू उत्पाद जैसे कि खाने के तम्बाकू पर 60% का कुल शुल्क प्रभार्य होगा।

111. हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क को गत वर्ष सितम्बर में 16% से घटाकर 12% किया गया था। मैं इस पर पुनः 16% की सामान्य सेनवेट दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा मोटर स्प्रीट पर भी 16% की पूर्व दर बहाल करने का प्रस्ताव है। शुल्क में वृद्धि का भार सिवाय कतिपय तकनीकी सुधारों के, उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

112. एल.पी.जी. पर 8% का उत्पाद-शुल्क वसूला जाता है। मैं यही दर कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जो इस समय उत्पाद-शुल्क मुक्त है।

113. वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में अलग-अलग प्रसंस्करणकर्ताओं से यौगिक आधार पर उत्पाद-शुल्क वसूल करने की एक विशेष स्कीम दिसम्बर, 1998 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के कार्यचालन में गंभीर खामियां आ गई हैं। अतः मैंने 1 मार्च, 2001 से पुनः अलग-अलग वस्त्र निर्माण प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए यथामूल्य शुल्क ढांचे को अपनाने का निर्णय किया है। अलग-अलग प्रसंस्करणकर्ताओं को कल्पित आधार पर निविष्टियों पर चुकाए गए शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाएगी।

114. एक पंजीकृत ट्रेड नाम के अधीन बेचे गए वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क छूट जारी रखने का कोई आर्थिक तर्काधार नहीं है। मैं ऐसे वस्त्रों पर 16% का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

115. लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों पर एक करोड़ रुपये तक उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है। इस छूट का आशय वास्तविक रूप से लघु उत्पादकों को वित्तीय मदद पहुंचाना था। मैं निम्नलिखित मदों के संबंध में इस छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें छूट का दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है:

- * सूती धागा
- * बाल या रोलर बीयरिंग
- * निजी इस्तेमाल के लिए शस्त्र व गोला बारूद।

116. दियासलाई पर उत्पाद शुल्क ढांचे में प्रत्येक 50 तीलियों के प्रति सौ डिब्बियों पर 25 पैसे से लेकर 2.40 रुपये तक की शुल्क की दरें शामिल हैं। मेरा विद्यमान दरों में युक्तिसंगतता लाकर एक अधिक युक्तिसंगत ढांचा लाने का प्रस्ताव है जिसमें हस्तनिर्मित क्षेत्रक के लिए 50 पैसे, मध्यम क्षेत्रक के लिए 1 रुपया और अर्द्ध-यांत्रिकीकृत क्षेत्रक के लिए 2 रुपये और यांत्रिकीकृत क्षेत्रक के लिए 3 रुपये की शुल्क दरें होंगी।

117. अध्यक्ष महोदय, उत्पाद-शुल्कों की दरों के मामले में सेनवेट की केवल एक बुनियादी दर और विशेष उत्पाद-शुल्क की एक दर लाकर मैंने इस दिशा में अपने आखिरी लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है। उत्पाद-शुल्क की कार्यविधियों को भी आधुनिक बनाया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा कर सकता हूँ कि उत्पाद-शुल्क अब विनिर्माण अवस्था तक मूल्यवर्धित कर का एक आदर्श नमूना है।

118. अब जिस अकेले मुद्दे को सुलझाया जाना बाकी है, वह व्यक्तिगत छूटों का मुद्दा है। छूटों की व्यवस्था अब अमल में लाए जा रहे एक सरल, साम्यपरक और युक्तिसंगत कर ढांचे के अनुकूल नहीं है। मैं छूटों को एकदम समाप्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह उनके लिए अप्रत्याशित आघात होगा जो छूटों के अभ्यस्त हो चुके हैं। परन्तु मैं उनको यह नोटिस

भी देना चाहूंगा कि वे औरों की तरह शुल्कों का भुगतान करने के लिए तैयार रहें। फिलहाल मैं चशमों, नकली आभूषण, रबरीकृत गद्दे आदि जैसे कुछ मदों पर 4% का मामूली शुल्क लगाकर एक साधारण शुरुआत कर रहा हूँ जिसे चार समान वार्षिक किस्तों में 16% कर दिया जाएगा। इस वृद्धिशील सूची में प्रतिवर्ष अधिकाधिक मदों को लाया जाएगा।

119. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं और सेवा क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मैं सेवा कर के दायरे का विस्तार कर रहा हूँ और मेरा निम्नलिखित सेवाओं को कर योग्य सेवाओं की सूची में लाने का प्रस्ताव है:

- विशिष्ट बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
- दुपहिया वाहनों सहित वाहनों की सर्विसिंग के लिए अधिकृत सर्विस स्टेशन
- पत्तन सेवाएं
- प्रसारण सेवाएं
- फोटोग्राफिक सेवाएं
- सम्मेलन आयोजन सेवाएं (कन्वेंशन सर्विसेज)
- साउंड रिकार्डिंग सेवाएं
- वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं
- टेलेक्स सेवाएं
- टेलीग्राफ सेवाएं
- प्रतिकृति सेवाएं
- ऑन-लाइन सूचना और डाटाबेस रिट्रीवल सेवाएं
- वीडियो टेप निर्माण सेवाएं
- बीमा अनुषंगी सेवाएं।

120. मैं लीज सर्किट लाइनधारकों को प्रदत्त सेवाओं को भी कर दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

121. अब मैं सीमा शुल्कों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

122. अपने पिछले बजटों में मैंने प्रमुख सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या कम करके चार कर दी है अर्थात् 35%, 25%, 15% और 5%। मेरी इस वर्ष सीमा शुल्क दरों की संख्या में और कमी करने की इच्छा नहीं है। तथापि, मैं 10% के अधिभार को आगे जारी न रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे सीमा शुल्क की अधिकतम दर मामूली रूप से गिरकर 38.5% से 35% हो जाएगी।

123. सभी कृषि उत्पादों पर पहले ही 35% या उससे अधिक की शुल्क की अधिकतम दर लागू है। प्रमुख अनाजों पर वर्तमान शुल्क दरें इस प्रकार हैं: गेहूँ (50%), चावल (70%/80%) और मक्का (50%)। मैं अब चाय, कॉफी, गरी और नारियल और सुखाए हुए नारियल पर सीमा शुल्क को वर्तमान 35% से बढ़ाकर 70% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

124. इसी प्रकार मैं कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क की दर जो इस समय 35% से लेकर 55% तक है, को बढ़ाकर 75% की एकरूप दर पर और रिफाईंड तेलों को 45%/65% से 85% पर लाने

का प्रस्ताव करता हूँ। विश्व व्यापार संगठन करार की बाध्यता के कारण सोयाबीन तेल पर 45% की न्यूनतर दर लागू होगी। मैं वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा कच्चे पॉम ऑयल के आयात पर सीमा शुल्क की दर को 25% से बढ़ाकर 55% करने का और इस रियायत को केवल रुग्ण वनस्पति इकाइयों तक सीमित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। अन्य इकाइयाँ 75% अदा करेंगी। मैं सदन को यह आश्वासन करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से जब कभी आयातों की वजह से कोई स्पष्ट खतरा नजर आएगा, हम तत्काल कदम उठाएंगे।

125. सदन को यह स्मरण होगा कि सरकार स्वयं आईटीए1 अनुसूची के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम उत्पादों तथा उनकी निविष्टियों और संघटकों पर सीमा शुल्क को 2003 तक समाप्त करने को वचनबद्ध है। इन उत्पादों पर सीमा शुल्क को 1 मार्च, 2001 से उनके वर्तमान स्तरों से घटाकर 15% पर लाने का प्रस्ताव है।

126. अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अप्रैल में शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद पुरानी कारें भी मुक्त रूप से आयात योग्य हो जाएंगी। पुरानी कारों के आयात में आने वाली तेजी की आशंका को दूर करने के लिए उनके आयात पर मूल सीमा शुल्क की दर को 105% तक बढ़ाया जाएगा जो शीर्ष दर की तीन गुना है। पुरानी कारों पर अब कुल शुल्क 180% से अधिक लगेगा। मैं पुराने बहु-उपयोगी वाहनों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों के आयात पर भी इसी प्रकार का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

127. घरेलू शराब उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं घरेलू उत्पादन पर राज्य उत्पाद शुल्क की लेवी को ध्यान में रखते हुए आयातित शराब पर उपयुक्त दर पर सीवीडी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

128. हमारे वस्त्र उद्योग को स्वयं आधुनिक बनना होगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा उत्पादन की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी होगी। मैं शटल रहित करघों सहित विनिर्दिष्ट कपड़ा मशीनों पर मूल सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। वस्त्र उद्योग क्षेत्र को और राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में मैं रेशम अपशिष्ट, कपास अपशिष्ट, पलैक्स फाइबर पर सीमा शुल्क को 35%/25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. जहां एक ओर कच्ची सामग्रियों तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच सीमाशुल्क में विसंगति के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अन्तिम उत्पाद के संबंध में भी यही स्थिति है। मानव निर्मित रेशों तथा धागों के उत्पादन हेतु डीएमटी, पीटीए, एमईजी और कैप्रोलैक्टम कच्ची सामग्रियाँ हैं। तथापि, इन सामग्रियों पर सीमाशुल्क रेशों तथा धागों पर लागू दर की अपेक्षा अधिक है। मैं डीएमटी, पीटीए, एमईजी और कैप्रोलैक्टम पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ और जो सिंथेटिक धागों और रेशों के लिए विश्व व्यापार संगठन की आबद्ध दर है। इसी प्रकार, सोडा कांच के सामान, डिटर्जेंट आदि के उत्पादन के लिए एक निविष्टि है और अन्तिम उत्पाद के साथ इस पर वर्तमान में अधिकतम 35% सीमाशुल्क लगाया जाता है। मैं इसे घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं रेशों और धागों के विनिर्माताओं के लिए पोलिएस्टर चिप्स और नाइलोन चिप्स पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

130. इसी प्रकार, उच्च कोटि के डीबीएम, सीवाटर मेग्नेशिया और फ्यूज्ड मेग्नेशिया पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% किया जा रहा है।

131. रत्न और आभूषणों के निर्यात के क्षेत्र में भारी सम्भावनाएं हैं। मैं काटे और तराशे गए रंगीन रत्नों पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इन विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूं जबकि इनका आयात रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। तराशे न गए हीरों पर सीमाशुल्क की दर अब 5% होगी।

132. सीएनजी किट और उनके पुर्जों में 5% का निम्न शुल्क लगता। मैं एलपीजी परिवर्तित किटों तथा उनके पुर्जों के संबंध में भी इसी व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं।

133. एलएनजी का उत्पादन भारत में नहीं होता। एलएनजी के आयात पर पड़ने वाले सीवीडी का भार एलएनजी परियोजनाओं की लागत को बढ़ा देता है। इसलिए मैं एलएनजी को सीवीडी से रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

134. इसी कारण से, मैं सीवीडी के प्रयोग से वैटल एक्सट्रैक्ट को रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

135. मैं सीमेंट तथा क्लिकर पर सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह कमी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सीमेंट की घरेलू कीमतों को आसान बनाने में मददगार होगी।

136. अध्यक्ष महोदय, अधिकृत प्रेसमैन और कैमरामैनों को अपने व्यावसायिक उपयोग हेतु सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना पांच वर्ष में एक बार एक लाख रुपये तक के मूल्य का कैमरा, कम्प्यूटर, फ़ैक्स मशीन आदि का आयात करने की अनुमति है। उनके द्वारा बहुत सारी उपयोगी अच्छी फोटो लेने को ध्यान में रखते हुए मैं इस पांच वर्ष की दीर्घकालिक प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

137. चलचित्र कला की बेहतर गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए मैं फिल्म उद्योग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सिने कैमरा, प्रोजेक्टर और अन्य संबद्ध उपस्करों पर सीमाशुल्क को 25% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूं।

138. मैं तरकरी को हतोत्साहित करने के लिए प्रति 10 ग्राम स्वर्ण पर 400 रुपये के शुल्क को घटाकर प्रति 10 ग्राम स्वर्ण पर इसे 250 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

139. कई उद्योग संघों ने सूचित किया कि आयातित उपभोक्ता उत्पादों पर सीवीडी को भी अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर लगाया जाए अन्यथा इसमें समानता नहीं आएगी। मैं उनकी युक्तिसंगत दलील को स्वीकार करता हूं। वित्त विधेयक में इस निर्णय को कार्यान्वित करने के समर्थकारी उपबंध निहित हैं।

140. मैं कुछ मदों पर सीमाशुल्क से रियायत हटाने और उन पर 5% का नाममात्र का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

141. मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि हमारा सीमाशुल्क पूर्वी एशियाई स्तरों पर लाया जाएगा। मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए अधिकतम 20% की दर के साथ दरों की संख्या का न्यूनतम स्तर तीन वर्षों के भीतर तक घटाना चाहूंगा। इसके लिए यथा-समय आगामी बजट में तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे।

142. महोदय, बेहतर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक दक्षता के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

143. केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं और अनुदेशों के एक नये मैनुअल का प्रकाशन 1 सितम्बर, 2001 में किया जाएगा। इसमें सरलता, संक्षिप्तता तथा पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा। मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को उपभोक्ता के अनुकूल बनाने हेतु सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्ताव से वर्ष में 4677 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सीमाशुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से 2128 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान है। मेरा अनुमान है कि अगले वर्ष अप्रत्यक्ष कर राजस्व 1,40,992 करोड़ रुपए होगा।

145. उत्पाद और सीमाशुल्कों में किए जाने वाले परिवर्तनों को प्रभावी बनाने हेतु जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

146. प्रत्यक्ष करों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मेरा बल कर दरों को स्थायित्व प्रदान करने, कर आधार को व्यापक बनाने, कर कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और उसका सरलीकरण करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने पर रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष कर राजस्व वर्ष 1998-99 में 46,428 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष अनुमानित 74,467 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों की संख्या मार्च, 1998 में एक करोड़ से काफी बढ़कर इस वर्ष के प्रारंभ में 2.3 करोड़ हो गई है। अतएव, मैं इस वर्ष भी वही दर जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, सहकारी समितियां अबसे 35% की बजाए 30% कर अदा करेंगी।

147. अपने वर्ष 1999-2000 के बजट में निगमों और गैर-निगमों पर 10% अधिभार लगाते समय मैंने यह वचन दिया था कि यह एक अस्थायी लेवी होगी। तथापि, मैं कारगिल के अप्रत्याशित व्यय भार के कारण उच्च आय स्तरों वाले गैर-निगम करदाताओं पर अधिभार की राशि में 15% की वृद्धि करने के लिए बाध्य हुआ था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मैंने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि हेतु गुजरात भूकंप राहत के लिए निगमों पर 1% का अधिभार और सभी करदाताओं पर 2% अधिभार बढ़ाया था। मैं अब गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की राहत के लिए 2% के अधिभार को छोड़कर निगमों और गैर-निगमों द्वारा देय सभी अधिभार हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। 60,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर यह अधिभार नहीं लगेगा।

148. महोदय, कल्याणकारी उपाय के रूप में, मैं मानसिक विकृति, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक रूप से कमजोर, और बहु अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट में दान देने के लिए शत-प्रतिशत छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

149. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि संभावित आयकर निर्धारितियों की पहचान करने और उन्हें कर-जाल में लाने के लिए वित्त अधिनियम, 1998 में लागू की गई छः में से एक की संशोधित योजना से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। अतएव मैं 1991 की जनगणना द्वारा यथापरिभाषित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में छः में से एक की योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2001 की जनगणना से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को बाद में शामिल किया जाएगा।

150. कतिपय कंपनियां अपनी आय की विवरणियां संभवतः इस दलील पर दाखिल नहीं कर रही हैं कि उनकी कोई कर-योग्य आय नहीं है। इस प्रकार ये कंपनियां राजकोषीय

अनुशासन से बाहर निकल जाती हैं और प्रारम्भिक वर्षों के दौरान उनके वित्तीय लेन-देनों की संवीक्षा नहीं हुई। अतएव, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभी कंपनियों को चाहे वे घाटा उठा रही हों, अपनी विवरणियां दाखिल करनी चाहिए।

151. महोदय, कर आधार को व्यापक बनाने का दूसरा प्रभावी उपाय स्रोत पर कर की कटौती का दायरा और बढ़ाना है। अब से शेयरों और प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देनों को छोड़कर कमीशन अथवा दलाली द्वारा 2500/- रुपए से अधिक की आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती 10% की दर पर होगी।

152. लाटरियों, वर्ग पहेलियों आदि से जीती गई राशियों पर अभी 40% की दर से कर लगता है। चूंकि सीमांतिक वैयक्तिक आयकर की दरें अब 30% पर स्थिर हो गई हैं इसलिए इस आय पर भी अब 30% की दर से कर लगेगा। आजकल टेलीविजन गेम शो बहुत लोकप्रिय हैं। मैं विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इनसे और ऐसे ही सभी गेम शो से जीती गई राशियों पर स्रोत पर 30% की दर से आयकर की कटौती की जाएगी।

153. इस समय बैंक अथवा आवास वित्त कंपनी के पास जमाराशियों के संबंध में आय 10,000 रुपए और अन्य मामलों में 5000/- रुपए से अधिक हो जाने पर सावधि जमाराशियों पर ब्याज से प्राप्त राशि पर स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। इन नई सीमाओं से कर आधार में कमी और जमाराशियों के विखण्डन के कारण कर-योग्य आय को कम सूचित करना प्रदर्शित हुआ है। अतएव, मैं सभी मामलों में इस सीमा को घटाकर 2500/- रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

154. आर्थिक उदारीकरण से वेतनभोगी वर्ग के वेतन पैकेज में कई परिवर्तन हो रहे हैं। इसे कई घटकों में विभाजित किया जा रहा है और नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही परिलब्धियों, लाभों अथवा सुविधाओं के स्वरूप को नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं। वेतन पैकेज के वर्तमान ढांचे के साथ अपनी कर प्रणाली को समरूप बनाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मकानों और कारों, जहां सरलता के लिए विभिन्न मानदंड अपनाए जाएंगे, से संबंधित मामलों को छोड़कर परिलब्धियों, लाभों अथवा सुविधाओं का मूल्य, नियोक्ता को आने वाली उनकी लागत के आधार पर निश्चित किया जाएगा।

155. महोदय, मैं एक लाख रुपए तक की आय वाली निम्न आय सीमा में वेतनभोगी व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन अपने पात्र निवेशों के संबंध में इस समय प्रदान की जा रही 20% की छूट की तुलना में 30% की दर पर वर्धित कर छूट प्राप्त करेंगे।

156. निर्यातोन्मुखी इकाइयां और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क में स्थित इकाइयों के मामले में घरेलू बाजार में उनकी बिक्री के 25% को कर से छूट दी जाती है। मैं ऐसी इकाइयों की घरेलू बिक्री से होने वाले लाभों के कराधान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

157. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहा है और उसे बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अतएव, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क में स्थित इकाइयों द्वारा 'कार्यस्थल पर' सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ उनके अन्य निर्यात आय के समान छूट के पात्र होंगे। इन क्षेत्रों से बाहर स्थित इकाइयां भी ऐसी निर्यात आय

पर कर छूट का लाभ प्राप्त करेंगी। मैं आगे यह प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख में कंपनियों के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित शर्त उन कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जिनमें जनता पर्याप्त रूप से दिलचस्पी रखती है।

158. "नाबार्ड", राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की आय को उनके कार्यकरण के प्रारम्भिक वर्षों में राजकोषीय समर्थन प्रदान करने की दृष्टि से छूट दी गई थी। अब ये संस्थाएं परिपक्व हो गई हैं और वाणिज्यिक आधार पर कार्यरत हैं। अतएव, मैं इन संस्थाओं को उपलब्ध कर संबंधी छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

159. कतिपय विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर देय ब्याज को इस समय कर से छूट प्राप्त है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि ऋणदाता द्वारा प्राप्त ब्याज उसके निवास देश में कर योग्य है और उसे भारत में उसके द्वारा अदा किए गए किसी कर के लिए क्रेडिट मिलेगा, भेजवान देश में कर देयता से कोई भी छूट ऋणदाता को कोई लाभ प्रदान नहीं करती परंतु उससे हमारे कर राजस्व में कमी ही होती है। अतएव, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर अदा किए गए ब्याज के संबंध में कर की छूट पहली जून, 2001 को अथवा उसके बाद लिए गए ऐसे उधारों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

160. इस समय 12,000 रुपए की सीमा तक कतिपय ब्याज संबंधी आय धारा 80ठ के अधीन छूट योग्य है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय भी 3000 रुपए तक छूट योग्य है। मैं इस छूट की अधिकतम सीमा घटाकर 9,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

161. घरेलू कंपनियों के लाभांशों के वितरण पर और म्यूचुअल फंडों तथा भारतीय यूनित ट्रस्ट की यूनितों के संबंध में आय पर देय कर को पिछले वर्ष 10% से बढ़ाकर 20% किया गया था। पूंजी बाजार के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मैं इस कर को घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. प्राथमिक निर्गमों में निवेशक की दिलचस्पी बहाल करने में सहायता देने के लिए मैं प्रतिभूतियों और यूनितों की विक्री से होने वाले दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों को छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ अगर ऐसे अभिलाभों का सरकारी कंपनियों के शेयरों के प्रारंभिक इशू में पुनः निवेश किया जाता है।

163. महोदय, आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए करावकाश के रूप में कर संबंधी प्रोत्साहन को और युक्तिसंगत और विस्तृत करने का प्रस्ताव किया जाता है। आधारभूत संरचना के मुख्य क्षेत्रों यथा, सड़कों, राजमार्गों, रेल प्रणाली, जल शोधन और आपूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों के लिए मैं अब दस-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे प्रारंभिक बीस वर्षों के दौरान लिया जा सकता है। विमानपत्तनों, पत्तनों, अन्तर्देशीय पत्तनों, और जलमार्गों, औद्योगिक पार्कों और विद्युत के उत्पादन और वितरण, जो दीर्घावधि में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बन जाते हैं, के मामले में प्रारंभिक पंद्रह वर्षों के दौरान लिए जाने वाले दस-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव किया जा रहा है। विद्युत और औद्योगिक पार्कों के लिए व्यापार को प्रारंभ करने की अवधि भी 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाई जा रही है।

164. दूरसंचार क्षेत्रक को पांच-वर्षीय करावकाश और आगामी पांच वर्षों के लिए 30% की छूट दिनांक 31 मार्च, 2000 तक उपलब्ध थी। मैं दिनांक 31 मार्च, 2003 को अथवा उसके

पहले अपना प्रचालन प्रारंभ करने वाली इकाइयों के लिए इस रियायत को भूतलक्षी प्रभाव से पुनः लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये रियायतें इंटरनेट सेवा प्रदायकों और ब्रॉडबैंड नेटवर्क को भी दी जाएंगी।

165. महोदय, आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रस्तावित करावकाश के अतिरिक्त, दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने वाले अथवा आधारभूत संरचना सुविधा प्रदान करने में संलग्न उद्यमों की इक्विटी पूंजी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। ब्याज, लाभांशों अथवा ऐसे निवेशों से दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों से होने वाली आय पूर्णतः छूट प्राप्त है। मैं आधारभूत संरचना उद्यमों से वित्तीय संस्थानों द्वारा अर्जित गारंटी कमीशन और ऋण वृद्धि फीस को यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। सहकारी बैंक भी अनुमोदित आधारभूत संरचना सुविधाओं में निवेशों से होने वाली अपनी आय पर छूट के पात्र होंगे।

166. वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होने के लिए हमारी कंपनियों को अनुसंधान और विकास के लिए अपना निवेश और व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय, कतिपय क्षेत्रों में कंपनियों के आंतरिक अनुसंधान और विकास पर व्यय के 150% की भारांशित छूट कंपनियों को अनुमत्य है। महोदय, मैं इस भारांशित छूट को जैव-प्रौद्योगिकी तथा नैदानिक परीक्षणों, पेटेंट दाखिल करने और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इंडिया मिलेनियम मिशन, 2020 के अधीन निर्दिष्ट परियोजनाओं को अदा की गई पूरी राशि 125% भारांशित छूट के लिए पात्र होगी।

167. औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने पिछले वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रचालनरत इकाइयों को दस वर्षों की अवधि के लिए निर्यात लाभों की 100% छूट प्रदान की थी। मैं अब इन क्षेत्रों के विकास के लिए और कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ। 10 वर्षीय करावकाश के रूप में आधारभूत संरचना के लिए उपलब्ध रियायतें उसी प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रवर्तकों को उपलब्ध होंगी जिस प्रकार वे औद्योगिक पार्क के प्रवर्तक को उपलब्ध होती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए दीर्घावधिक निवेश करने वाले निवेशकों की आय को भी छूट प्राप्त होगी।

168. खाद्यान्नों का भंडारण और उनकी ढुलाई हमारी मुख्य चिंता है। महोदय, मैं खाद्यान्नों की संभाल, ढुलाई और भंडारण के एकीकृत व्यापार में लगे उद्यमों को आगामी पांच वर्षों के लिए पांच वर्षों का करावकाश और लाभों पर 30% की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

169. महोदय, उन उद्योगों का संवर्धन करने के लिए जो ताजगी प्रदान करने वाले चाय का प्याला देते हैं, मैं चाय के लिए उपलब्ध विकास संबंधी छूट को 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस अतिरिक्त छूट का प्रयोग केवल पुनःबागवानी, कायाकल्प करने और चाय बागानों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।

170. नौवहन उद्योग की लंबे समय से मांग रही है कि जहाजों और अन्तर्देशीय जल पोतों के संबंध में उपलब्ध मूल्यहास की दर बढ़ाई जाए। मैं मूल्यहास की दर 25% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

171. वस्त्रोद्योग क्षेत्र के बुनाई, प्रसंस्करण और वस्त्र क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन खरीदे गए संयंत्रों और मशीनरी पर 50% की दर पर त्वरित मूल्यहास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

172. इस समय मंदी का सामना कर रहे वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं एक वर्ष के लिए नए वाणिज्यिक वाहनों पर 50% की दर से त्वरित मूल्यहास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

173. मेरे पहले के प्रत्येक तीनों बजटों ने आवास क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाने की व्यवस्था की है। महोदय, इस प्रथा को जारी रखते हुए, मैं स्वयं के कब्जे वाले आवासों के लिए आवास ऋणों पर देय ब्याज की छूट की अधिकतम राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

174. गृह संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मरम्मत आदि के लिए वार्षिक मूल्य के 25% की वर्तमान छूट बढ़ाकर 30% किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, आवास ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर किए जाने वाले व्यय को छोड़कर कोई और छूट नहीं होगी।

175. मैं जीवन बीमा निगम के प्रीमियम के भुगतानों पर छूट के रूप में अनुमत्य कर प्रोत्साहन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सभी बीमा कंपनियों को देने का प्रस्ताव करता हूँ।

176. भारत में बहुराष्ट्रीय उद्यमों की उपस्थिति और अन्तर-समूह लेन-देनों में कीमतों के नियंत्रण द्वारा विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लाभ आवंटित करने की उनकी योग्यता ने अंतरण मूल्यनिर्धारण के मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। मैंने अंतरण मूल्य-निर्धारण के मुद्दे की जांच करने के लिए नवम्बर, 1999 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। उनकी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें अंतरण मूल्य-निर्धारण विधान के लिए विस्तृत ढाँचे का प्रस्ताव किया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर वित्त विधेयक में आवश्यक विधायी परिवर्तन किए जा रहे हैं।

177. विदेशी टेलीविजन प्रसारण चैनलों पर अब से आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित उनकी आय पर भारत में कर लगाया जाएगा।

178. महोदय, मैं ऐसे कई उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ जो करदाता के अनुकूल हों। आयकर विभाग द्वारा वापसी देने, पुनःनिर्धारण करने और निर्धारणों को पुनःखोलने के लिए समय सीमा कम किया जाना प्रस्तावित है। विभाग को अब किसी निर्धारिती को देय वापसी राशि रोकने का भी अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के स्थानान्तरण से पूर्व निर्धारणकर्ता अधिकारी से धारा 230क के अधीन कर निपटान प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी। मैं दंड की मात्रा का निर्णय करने के लिए इस समय उपलब्ध विवेकाधिकार को भी हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से अधिकांश चूकों के लिए दंड की नियत राशि देय होगी।

179. कर छूट प्राप्त करने के लिए कतिपय शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। इस समय इन संस्थानों को अनुमोदन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपना आवेदन दाखिल करना होता है। महोदय, मैं यह अधिकार मुख्य आयुक्त, आयकर को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

180. महोदय, प्रत्यक्ष करों पर इस बजट में किए गए मेरे प्रस्तावों से 5,500 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी, जिसे मैं कर वसूली में तेजी और वर्धित स्वैच्छिक अनुपालन से पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा अनुमान है कि वर्ष 2001-2002 में प्रत्यक्ष कर राजस्व की राशि 84,800 करोड़ रुपये होगी।

181. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों से मैं केन्द्र के लिए 163031 करोड़ रुपए की कुल कर राजस्व प्राप्तियों और 116314 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद के 4.7% के राजकोषीय घाटे का अनुमान करता हूँ। मैंने इससे कम राजकोषीय घाटे की व्यवस्था की होती परन्तु वह केवल विकास को जोखिम में डालकर ही संभव होता, जो अस्वीकार्य था।

182. यह बजट आर्थिक सुधारों के द्वितीय चरण को आगे ले जाने के लिए है। यह प्रगति और विकास का बजट है। यह क्षमता के साथ समानता के लिए बजट है। यह नई सहस्राब्दी में भारत के लोगों के नई आशाएं प्रदान करने वाला बजट है।

183. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस महान सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

डी. स्वरूप, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(Budget Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2001

No. 15(5)-B(D)/2001.—The following is published for general information :—**Budget 2001-2002****Speech of Shri Yashwant Sinha, Minister of Finance**

28th February, 2001

PART A

Sir, I rise to present the Budget for the year 2001-2002.

2. I do so in all humility. The challenges we face this year are awesome, made more so by the tragedy and devastation caused by the Gujarat earthquake. I hope I shall get the understanding and support of the whole House in my endeavour to meet these challenges.

ECONOMIC CONTEXT

3. The Indian economy has continued to exhibit both growth and resilience that have characterized its performance in the past few years. Overall economic growth this year is expected to be about 6 per cent despite a series of unexpected setbacks. We have had a second successive year of irregular monsoon resulting in low agricultural growth. World petroleum prices have continued to stay at high levels placing strains on the economy as a whole, and have led to a significant increase in inflation over the past year. Fortunately, despite the increase in energy prices, the prices of essential commodities, and of manufactured products as a whole, have remained stable. Inflation, excluding energy, was around 4 per cent during the year. The economy remained secure with record levels of foreign exchange reserves and public food stocks. The creditable export performance recorded last year improved further: exports grew by over 20 per cent in dollar terms in April-December 2000.

4. It is now 10 years since economic reforms began in 1991. During this period, the economy has grown at an average rate of 6.4 per cent per year since 1992-93 compared to the 5.8 per cent recorded in the 1980s. Poverty has fallen from 36 per cent in 1993-94 to 26 per cent or less now.

5. While economic reforms have placed the country on a much more secure and sustained growth path, we still have some serious concerns and cannot afford to be complacent.

- Agricultural reforms have been inadequate and our agriculture continues to be subject to the vagaries of the monsoon.
- Despite major industrial sector reforms, industrial growth has not accelerated to the double-digit level as expected.
- Inadequate fiscal adjustment has remained the most intractable problem over the past decade.
 - ♦ Interest payments now constitute over 69 per cent of the Centre's tax revenues.
 - ♦ Subsidies continue to increase to unaffordable levels and do not necessarily reach the deserving beneficiaries.
 - ♦ The pension liability of the Government is becoming onerous.
- Public investment in infrastructure and social sectors is inadequate due to falling total public sector savings.
- Private investment is constrained due to high real interest rates and inadequate infrastructure.

BUDGET STRATEGY

6. Thus, despite the many achievements of economic reforms over the past decade, much remains to be done if we have to achieve our full potential. There is urgent need to further deepen reforms to set the stage for higher growth over the next decade. We have to intensify our effort in fiscal adjustment so that the generations to come are not burdened by our borrowing excesses. The economy has achieved significant acceleration in growth over the last 20 years. Our aspiration must be to achieve still higher growth in the next 20 years.

7. The broad strategy of the budget, therefore, with this objective of growth in mind is to ensure:

- Speeding up of agricultural sector reforms and better management of the food economy.
- Intensification of infrastructure investment, continued reform in the financial sector and capital markets, and deepening of structural reforms through removal of remaining tiresome controls constraining economic activity.
- Human development through better educational opportunities and programmes of social security.
- Stringent expenditure control of non-productive expenditure, rationalisation of subsidies and improvement in the quality of Government expenditure.
- Acceleration of the privatisation process and restructuring of public enterprises.
- Revenue enhancement through widening of the tax base and administration of a fair and equitable tax regime.

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

8. As I have noted, reforms in the agriculture sector have been inadequate and must be speeded up. The Government has already announced the first ever National Policy in Agriculture.

9. The provision of adequate credit flow is critical for agricultural production. Total credit flow to agriculture through institutional channels of commercial banks, cooperative banks and regional rural banks is estimated to have reached a level of Rs 51,500 crore this year, an increase of about 15 per cent over last year. It is expected to increase to Rs 64,000 crore in 2001-2002 representing an increase of 24 per cent. In order to ensure continued healthy growth of the agricultural sector, I propose the following steps:

- The operation of the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), set up in 1995-96 with NABARD, has been very successful in upgrading rural infrastructure with about 1,84,000 projects sanctioned so far. To help the States, I have decided to reduce the interest rate charged by NABARD from 11.5 per cent to 10.5 per cent. The corpus of RIDF VII will be increased from Rs 4500 crore to Rs 5000 crore next year.
- The innovation of **Kisan Credit Cards** has proved to be very successful. Since the year of its introduction in 1998-99, almost 110 lakh of KCCs have been issued. I am asking our banks to accelerate this programme and cover all eligible agricultural farmers within the next 3 years.
- I am also asking the banks to provide a personal insurance package to the KCC holders, as is often done with other credit cards, to cover them against accidental death or permanent disability, upto maximum amount of Rs 50,000 and Rs 25,000 respectively. The premium burden will be shared by the card issuing institutions.
- NABARD and SIDBI were asked to link one lakh Self-Help Groups during the current year. NABARD by itself is well poised to exceed this target by the end of next month. I expect NABARD to link 1 lakh additional Self Help Groups during 2001-02, which would help in providing access to credit to an additional 20 lakh families. Share-croppers and tenant farmers will also become eligible for this scheme and special attention will be given to SC/ST groups. A micro finance development fund has also been set up in NABARD with contribution of Rs 40 crore each by NABARD and RBI.
- I had permitted NABARD to issue capital gains tax exemption bonds last year. This has helped NABARD to mobilise more than Rs 1000 crore at lower than normal interest rates thereby reducing its cost of funds. I propose to continue with this tax exemption.
- The resources from the Watershed Development Fund set up in NABARD would be used to promote people's participation and also enable water users' associations to implement, operate and maintain irrigation schemes.

10. In 1999, I had announced a credit linked subsidy scheme for construction of cold storages for perishable commodities. So far, NABARD and NCDC have provided Rs 161 crore of credit for creation of additional capacity of 9.69 lakh tonnes. A subsidy of Rs 78 crore for setting up these cold storages was provided during 2000-2001. I now propose to extend the coverage of this scheme to also cover rural godowns. The subsidy to be provided by the Government would be suitably enhanced to take care of increased coverage. The loans would carry an adequate long-term repayment period and would enable individuals, cooperative societies and others to build godowns by availing of loans from cooperative banks, commercial banks and RRBs.

11. This scheme will enable small farmers to enhance their holding capacity in order to sell their produce at remunerative prices. NABARD proposes to reduce its rate of interest for funding the storage of crops, from 10 per cent to 8.5 per cent. Small farmers will particularly benefit from this scheme by avoiding distress sales.

12. With the diversification and modernisation of agricultural practices, there is a need to augment support and extension services for agriculture. For this purpose, a scheme for setting up Agriclincs and Agribusiness Centres by agricultural graduates will be launched with the support of NABARD. These centres will provide a package of soil and input testing facilities and other consultancy services. They will strengthen transfer of technology and extension services and also provide self-employment opportunities to technically trained persons. Loans on attractive terms for setting up these centres will be provided by banks with refinance from NABARD.

13. There is a significant potential of improving crop productivity in the Eastern and North Eastern regions through crop diversification and adoption of improved technologies. These regions also have large untapped ground water resources. A sum of Rs 61 crore has been provided for the Centrally Sponsored Scheme on "On-Farm Water Management for Increasing Crop Production in Eastern India".

14. I am also happy to inform the House that I have provided Rs 38 crore for the "Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in the North-Eastern States", announced by me last year.

Rural Roads

15. In my last Budget, I had announced the launching of a new scheme, the **Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY)** with the objective of undertaking time bound programmes to fulfill the critical needs of the rural people. As a follow up, particularly with the objective of achieving rural connectivity, the **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana** has been launched by the Hon'ble Prime Minister on December 25, 2000. A Central allocation of Rs 2500 crore was provided for 2000-01. I am providing another allocation of Rs 2500 crore for the coming year. 50 per cent of the diesel cess is earmarked for development of rural roads.

Rural Electrification

16. It is a matter of concern that even after 50 years of planned development there are still about 80,000 villages, which do not have access to electricity. A package of initiatives is therefore being launched to improve the power distribution system in rural areas. This includes:

- Completion of electrification of bulk of the remaining villages in the next 6 years.
- Extension of assistance to the States for village electrification works under the PMGY whose funding is being augmented.
- Stepping up credit support from Rural Electrification Corporation to SEBs for speedy electrification of dalit bastis, households of scheduled tribes and other weaker sections of society.
- Improving the quality of power supply in villages, augmentation of distribution networks in rural areas supported by REC under the Accelerated Power Development Programme.
- Earmarking a sum of at least Rs 750 crore out of RIDF for rural electrification works.
- Augmenting the resources of REC, by allowing it to float capital gains tax exemption bonds along with NABARD and NHAI under Section 54 EC of the Income Tax Act.

Management of the Food Economy

17. Increased production and rising productivity makes the proper management of the food economy more critical than ever before. Our policy has to be transformed to deal with surpluses rather than only shortages. The present arrangement of Government of India procuring foodgrains and States managing the PDS has led to many problems. While the subsidy has increased from Rs 8210 crore at B.E. to Rs 12,125 crore at R.E. stage this year, the satisfaction level has gone down. I propose, therefore, to give an enlarged role to the State Governments in both procurement and distribution of foodgrains for PDS in their respective states. Instead of providing subsidised foodgrains, financial assistance will be provided to the State Governments to enable them to procure and distribute foodgrains to BPL families at subsidised rates. FCI will continue to procure foodgrains for maintaining food security reserves and for such State Governments who will assign it this task on their behalf. Details for operationalising these arrangements will be worked out in consultation with the State Governments at the earliest.

18. The agricultural sector continues to be constrained by the existence of a number of inhibiting controls and regulations. The Essential Commodities Act, 1955 provides for the control of production, supply and distribution of certain commodities identified as essential commodities under the Act to protect the interest of consumers. State Governments have issued a large number of Control Orders under this Act inhibiting free movement of some food and agriculture products. In the changed present situation undue restrictions on movement and stocking of foodgrains and agricultural produce is acting as a disincentive to farmers.

19. Government therefore proposes to review the operation of the Essential Commodities Act, 1955 and remove many of the restrictions that have been imposed on the free inter-State movement of foodgrains and agricultural produce and also on the storage and stocking of such commodities. It will also review the list of commodities declared as essential under the said Act and bring their number down to the minimum required. My colleague the Food Minister will issue necessary directions in this regard after consultations with the State Governments.

INFRASTRUCTURE

20. Rapid development of the economy depends on adequate investment in infrastructure. A key issue here is imposition of appropriate user charges necessary to provide adequate returns on investment. Public resources have been invested in the public sector over the last 50 years for the provision of infrastructure services in the country. One consequence of this has been that user charges have inevitably become politically determined. Over time non-merit subsidies inherent in such low user charges have mounted to over 10 per cent of GDP, a figure similar to the total fiscal deficit of the Central and State Governments combined. Hence they are a major cause of the fiscal distress being experienced at all levels.

21. I believe that this issue is now so important that it needs urgent discussion throughout the country. The challenge is to achieve a consensus on the imposition of appropriate user charges in such a manner that the poor are protected while those who can pay are made to do so. Only then will we be able to accelerate investment in these essential services in both the public and private sectors. A prime example of this is the power sector.

Power

22. The importance of power in fuelling economic growth cannot be over emphasised. The total cost to the State Electricity Boards of implicit subsidies amounts to about Rs 36,000 crore this year. After accounting for cross subsidy and State subventions, actual commercial losses of all SEBs combined are estimated to be about Rs 24,000 crore. Hidden in these loss figures are extremely high T&D losses.

23. Although all of these losses are borne by SEBs and State Governments, I have to express my concern on this issue since this is a massive national loss and affects Central Government undertakings also. The total dues owed to Central Government utilities by SEBs and others now amount to over Rs 25,000 crore. If these resources were available, the country would have no difficulty in investing adequately in power sector expansion to the benefit of all. Theft of electricity must be stopped and economic tariffs levied.

24. The most vital element of the reform process is the restoration of financial viability of the State Electricity Boards (SEBs). On the basis of consensus that has progressively emerged in the National Development Council Resolution of 1992, the Common Minimum National Action Programme drawn up in 1996

and the Power Ministers' Conference of February 2000, the Central Government is accelerating the programme of reforms in SEBs on the basis of specific milestones that are being built into MOUs entered into with State Governments. These MOUs include specific milestones such as:

- A time bound programme for installation of 100 per cent metering by December 2001.
- Energy audit at all levels.
- A specific programme for reduction and eventual elimination of power theft.
- Tariff determination by SERCs and compliance thereof.
- Commercialisation of distribution and
- SEB restructuring.

To demonstrate the importance of this task, the Prime Minister will hold a meeting of State Chief Ministers on March 3, 2001.

25. MOUs have already been entered into with 5 States and we expect more States to adopt the reform process. Accordingly, plan allocation to the Accelerated Power Development Programme (APDP) has been stepped up to Rs 1500 crore next year from a level of Rs 1000 crore this year. Priority under APDP would be given to those states that undertake such reform. The key to restoration of financial viability is reform of distribution. Assistance from the Fiscal Reform Incentive Fund recommended by the 11th Finance Commission would also, inter-alia, be linked to the achievement of power reforms. The reforming States would also receive support from the Central Government in form of preferential allocation of power to SEBs from CPSUs, additional investment by CPSUs in generation and transmission, and preferential allocation of external aid.

26. In order to help accelerate the reform process in the power sector and to unify all existing central legislations in the sector, my colleague the Minister for Power will introduce the Electricity Bill 2001 within this session.

27. The Plan outlay for central sector power utilities is being raised from Rs 9,194 crore this year to Rs 10,030 crore for 2001-02. This demonstrates the commitment of the Central Government to accelerate public sector power investment along with power sector reforms.

Roads

28. The National Highway Development Programme (NHDP) represents a new road vision for this country. Its unprecedented scale is symbolic of government's earnestness to provide connectivity and mobility of an altogether different order. The key to government's success in accelerating the road development programme lies in its bold policy of levying a cess on petrol and diesel as a user charge for road usage. Resources for Phase I, to be completed

by December 2003, have already been tied up. Work has already been awarded for more than 1500 Kms. of the golden quadrilateral in addition to the completed sections totalling 600 Kms. The balance portion is expected to be awarded by the middle of this year.

29. The cess has paved the way for integrated road development in the country, including village roads, district roads, state roads, and national highways. Rs 962 crore from the cess fund is being made available to States for state roads. The total plan outlay for this sector is being enhanced by 93 per cent to Rs 8727 crore in 2001-02.

Telecom

30. Another area of success is in the telecommunications sector. Almost all the policy measures announced in the New Telecom Policy 1999 regarding basic and cellular services, national long distance, Internet services, and corporatisation of Department of Telecom Services have been implemented. Competition is being introduced in all service segments.

31. By March 2001, overall teledensity is expected to reach 3.5 per hundred, about double the teledensity of only two years ago. Moreover, the new competition has already reduced prices for consumers. There are now almost 800,000 STD/ISD/Local booths around the country bringing telephone service within reach of almost all consumers, apart from generating considerable employment.

32. Looking ahead, having recognised the imperatives of technological change in this area, the Government proposes to introduce the Convergence Bill to cover telecommunications, information technology, and information and broadcasting sectors in an integrated manner.

Ports

33. Coming to the port sector, I am glad to report that policy initiatives designed to increase private sector participation in ports have also been successfully implemented. Overall, capacity in Indian major ports is expected to go up to 314 million tonnes this year and further to 376 million tonnes by the end of 2001-2002, along with substantial capacity addition in minor ports. There is now adequate capacity in major ports. Ships no longer have to wait for berths as was the case before.

34. Ennore port has already been corporatised and Jawahar Lal Nehru Port in New Mumbai is next, and with experience, other major ports can also be corporatized, enabling them to raise resources in the market. Successful investment is being enabled by the setting of economic tariff levels. With the formation of the Tariff Authority for Major Ports, these tariffs are being rationalised further on a continuing transparent and fair basis.

FINANCIAL SECTOR AND CAPITAL MARKETS

35. A great deal of progress has been made over the last few years in pursuing reforms in the financial sector and capital markets. I propose to continue reform in this sector.

Debt Market

36. The Indian equity market is the oldest in Asia. Since the creation of SEBI much greater transparency as well as automaticity has been introduced in the working of the equity market. The need now is to develop and deepen the debt market. This will be of great benefit to small investors and institutional investors alike. The infrastructure sector will be enabled to raise long term funds, particularly with the opening of the insurance sector.

37. In order to further develop a transparent and active debt market in general, and the Government securities market in particular, I propose to take the following measures:

- A Clearing Corporation will be set up under the active encouragement of the RBI, with State Bank of India as the chief promoter, and is expected to be in place by June 2001. It will also enable settlement of forex transactions.
- Trading of Government Securities, through order driven screen-based system will be implemented.
- An electronic Negotiated Dealing System will be set up by the RBI by June 2001 to facilitate transparent electronic bidding in auctions and dealings in Government securities on a real time basis.
- In order to ensure smooth and quick movement of funds, the Electronic Fund Transfer (EFT) and Real Time Gross Settlement Systems (RTGS) are being put in place by the Reserve Bank of India within the next year.
- Clarifications are being issued by CBDT to promote the issuance of STRIPS, zero coupon bonds, deep discount bonds, and the like.
- The old Public Debt Act will be replaced by Government Securities Act.
- Comprehensive legislation will be introduced on securitization.

38. I propose to set up a small group comprising the Reserve Bank of India, SEBI, the stock exchanges and Ministry of Finance to monitor and implement these developments so that the debt market becomes active next year.

Banking Sector

39. Banking sector reforms have proceeded apace in a phased manner over the past decade. However, the problem of non-performing assets with banks has continued. Special attention is being paid to recovery of NPAs:

- Public Sector Banks have recovered Rs 800 crore of NPAs from 2 lakh accounts in 2000-01.
- Net NPAs as percentage of net advances were almost half at 7.4 per cent in 1999-2000 compared to 14.5 per cent in 1993-94.
- 22 Debt Recovery Tribunals (DRTs) and 5 Appellate Tribunals have been established.
- 7 more DRTs will be set up during 2001-02.

40. I also propose to bring in a legislation that will facilitate foreclosure and enforcement of securities in cases of default in order to enable the institutions to realise their dues.

41. In the light of new competition in the banking industry it is necessary to strengthen the management of the public sector banks. I propose to provide greater autonomy to bank managements. It is also essential to provide greater independence to bank managements in forming their own recruitment strategy and in implementing it. I therefore propose to abolish the Banking Services Recruitment Boards. This will be done in association with the Reserve Bank of India by July 31, 2001 or earlier. All future recruitments will be done by banks themselves.

Capital Account Liberalisation

42. Until about 10 years ago, all foreign exchange transactions were tightly controlled by the government and by the RBI. We have progressively loosened these controls and made the current account completely convertible. We have also liberalised the capital account for certain purposes. I propose to take further measures for liberalising the capital account. These are:

- Indian companies wishing to invest abroad may now invest up to US \$50 million on an annual basis through the automatic route without being subject to the three year profitability condition.
- Companies which have issued ADRs/GDRs may henceforth make foreign investments up to 100 per cent of these proceeds; up from the current ceiling of 50 per cent.
- Companies with proven track record wishing to invest larger amounts may now get a block allocation in advance from the RBI for investments overseas.
- Indian companies that have issued ADRs/GDRs may acquire shares of foreign companies up to an amount of US \$100 million or an amount equivalent to ten times of their exports in a year, whichever is higher.
- ADRs/GDRs will be provided two-way fungibility. Converted local shares may be reconverted to ADRs/GDRs while being subject to sectoral caps, wherever applicable.

- Indian companies will now be permitted to list in foreign stock exchanges by sponsoring ADR/GDR issues against block share holding. This facility would have to be offered to all categories of shareholders.

The Reserve Bank of India will be issuing these guidelines separately.

43. Investments by Registered partnership firms and companies providing professional services have not, so far, been permitted to make overseas investments. This ban is now being removed. Similarly, Indian employees who have the benefit of ESOP schemes in foreign owned companies can now make investments abroad up to US \$20,000 annually instead of in a block of 5 years.

Foreign Investment

44. Progressive liberalization has taken place in the provisions relating to foreign investment. I propose to take the following further measures:

- Foreign Institutional Investors (FIIs) can invest in a company under the portfolio investment route up to 24 per cent of the paid up capital of the company. This can be increased to 40 per cent with the approval of the General Body of the shareholders by a special resolution. I propose to increase this limit to 49 per cent
- Foreign Direct Investment (FDI) in Non-Banking Financial Companies (NBFCs) is permitted on a case by case basis upto 100 per cent but with a condition that a minimum of 25 per cent of their holding is divested in the domestic market. This condition is being removed, provided the foreign investors bring in a minimum of US \$50 million. FDI in NBFCs will now be put on the automatic route subject to RBI guidelines.

STRUCTURAL REFORMS

45. In order to accelerate growth in the Indian economy, we have now to address some of the difficult areas of reform that have not been tackled so far.

46. There are four significant areas where a price and distribution control regime exists. These are the areas of petroleum, fertilizer, sugar and drugs.

Administered Pricing Mechanism (APM)

Petroleum

47. As Hon'ble Members are aware, Government had, in November 1997, notified the details of dismantling of the Administered Pricing Mechanism (APM) in the petroleum sector by March 2002. I propose to adhere to this deadline. A time bound action programme is being prepared for the deregulation of APM by March, 2002. My colleague the Minister of Petroleum and Natural Gas will be outlining the road map for this separately.

Fertilizer

48. Hon'ble Members will recall that I have in the past referred to the rationalisation of fertilizer pricing with the objective of phasing out the existing retention price scheme (RPS) in the medium-term. Government has now decided to implement the recommendations of the Expenditure Reforms Commission for a phased programme of complete decontrol of urea by April 1, 2006. The following steps would be taken in the first phase commencing from April 1, 2001:

- The unit specific RPS will be replaced by a Group Concession Scheme. The current MRP arrangement will be continued and the concession for each group calibrated to enable the units to sell urea at the stipulated MRP.
- The rate of concession for urea units based on naphtha/FO/LSHS will be linked to international prices of these feed stocks.

Sugar

49. Government is committed to complete decontrol of sugar. But this must be irreversible. Government has decided to introduce futures/forward trading in sugar within the coming year, a step that is necessary before full decontrol. Sugar under the Public Distribution System will continue to be supplied to ration cardholders in the special category states, hill states, island territories and to BPL families in other states and UTs. Such supplies can even continue after sugar is completely decontrolled. The retail issue price of sugar under the PDS is being revised to Rs 13.25 per kg. with effect from March 1, 2001.

Drug Price Control

50. The domestic drugs and pharmaceutical industry needs support in order to meet the challenges and to avail of the opportunities arising out of liberalisation of our economy and the impending advent of the product patent regime. Government has been considering measures to lessen the rigours of the present price control mechanism where they have become counter productive. Towards this end, we have decided that the span of price control will be reduced substantially. However, keeping in view the interest of the weaker sections of society, Government will retain the power to intervene comprehensively in cases where prices behave abnormally. Changes in the Pharmaceutical Policy are being made accordingly.

Industrial Restructuring

51. Government had constituted a high level committee on law relating to revival, reconstruction and/or winding up of companies. The Committee has submitted its report and Government has accepted its key recommendations. It is proposed to repeal the SICA and also to amend the Companies Act in order to set up a National Company Law Tribunal. These legislative proposals are proposed to be introduced during the current session by my colleague, the Minister for Law, Justice and Company Affairs.

Labour Market

52. Along with these changes, it is also necessary to address the contentious issue of rigidities in our labour legislations. Some existing provisions in the Industrial Disputes Act have made it almost impossible for industrial firms to exercise any labour flexibility. The Government is now convinced that some change is necessary in this legislation. Chapter VB of the ID Act stipulates that employers in specified industrial establishments must obtain prior approval of the appropriate government authority for effecting lay-off, retrenchment and closure, after following the prescribed procedure. It is proposed that these provisions may now apply to industrial establishments employing not less than 1000 workers instead of 100. The separation compensation will be increased from 15 days to 45 days for every completed year of service. The enhancement of compensation would act as a deterrent on employers to take recourse to lay-off, retrenchment and closure in a routine manner.

53. Similarly, rigidities inherent in the existing legislation regarding Contract Labour inhibit growth in employment in many service activities. Section 10 of the existing Act envisages prohibition of contract labour in work/process/operation if the conditions set therein like perennial nature of job etc. are fulfilled. Section 10 enables the contract labour engaged in prohibited jobs to become direct employees of the principal employer. To overcome this difficulty and at the same time ensure the protection of labour, it is proposed to bring an amendment to facilitate outsourcing of activities without any restrictions as well as to offer contract appointments. It would not differentiate between core and non-core activities, and provide protection to labour engaged in outsourced activities in terms of their health, safety, welfare, social security, etc. It would also provide for larger compensation based on last drawn wages as retrenchment compensation for every year of service.

54. These measures will promote industrial investment in labour intensive, and export oriented activities providing for renewed industrial growth, while, at the same time safeguarding the interest of workers. My colleague, the Minister for Labour will introduce appropriate legislation to amend the Industrial Disputes Act and Contract Labour Act within this session.

Ashraya Bima Yojana

55. I am conscious of the short-term impact on organized labour force of the on-going liberalization of the economy. I therefore propose to introduce a new scheme of group insurance viz. "**Ashraya Bima Yojana**" to extend security cover to such affected workers. The policy will provide compensation of up to 30 per cent of last drawn annual pay for a period of one year to workers who lose their jobs. It is proposed that the policy will initially cover all employees drawing a salary up to Rs 10,000 per month. The four Government owned general insurance companies will administer this policy on a "No Profit No Loss" basis and will announce full details including premium rates of the proposed policy by the end of June 2001.

Small Scale Industries

56. Government's commitment to the Small Scale sector has been repeatedly demonstrated. A comprehensive policy package for this sector was announced by the Prime Minister on 30, August, 2000.

57. In order to encourage production and employment in this sector, the exemption limit has been doubled to Rs 1 crore from September 1, 2000.

58. The new Credit Guarantee Scheme of August 2000 has been provided budgetary support of Rs 100 crore in the current year. The limit of loan without collateral which was earlier fixed at Rs 10 lakh has been raised to Rs 25 lakh under this scheme. Already 7 banks have entered into an agreement with the Credit Guarantee Fund Trust that has been created to implement the scheme. A credit linked capital subsidy scheme for technology upgradation was launched in October 2000 envisaging 12 per cent capital subsidy. It is expected that loans to the extent of Rs 5000 crore would be made available to the SSI sector over the next 5 years under the scheme.

59. Our small-scale entrepreneurs have proved their competitiveness in providing over 35 per cent of national exports. To enable further new investment and technology upgradation in some of the key export oriented sectors, it is now proposed to dereserve another 14 items related to leather goods, shoes and toys.

Textiles

60. The Government has recently announced a New Textile Policy aimed at preparing industry for the new challenges of global competition. I am happy to announce a textile package comprising the following schemes:

- A scheme for setting up Integrated Apparel Parks is being initiated. This will enable the dereserved readymade garment industry to set up modern units with the best infrastructure. A budget provision of Rs 10 crore has been provided for the year 2001-02.
- A strong and modern weaving sector is very critical for this purpose. At least 50,000 new shuttleless looms and the modernisation of 2.5 lakh plain looms to automatic looms is expected to take place by 2004 through funding from the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS). The budget provision under TUFS is being raised from Rs 50 crore this year to Rs 200 crore in the next year.
- The Cotton Technology Mission is being continued and strengthened. The budget provision is being increased from Rs 15 crore to Rs 25 crore.
- The budget allocation for Ministry of Textiles is being enhanced substantially from Rs 457 crore in 2000-01 to Rs 650 crore in 2001-02.
- I shall provide the details of the proposed fiscal changes in Part B of my speech.

HUMAN DEVELOPMENT

Health and Family Welfare

61. Recognizing the need for increasing investments in social sectors, the Plan allocation for the Ministry of Health & Family Welfare has been stepped up from Rs 4920 crore to Rs 5780 crore. This includes an allocation of Rs 180 crore for HIV/Aids Control Programme.

Indian System of Medicine

62. There is now a great interest worldwide in herbal products as people look for gentler forms of treatment devoid of side effects. We are establishing a Traditional Knowledge Digital Library to bring the knowledge already in the public domain in international languages to prevent the grant of patents. We are also introducing a new scheme for strengthening the State Drug Testing Laboratories and pharmacies. We propose to provide Indian Systems of Medicine and Homeopathy benefits similar to the pharmaceutical industry.

Education

63. An integrated National Education Programme – the Sarva Siksha Abhiyan has been launched for universalising elementary education and a National Mission constituted with the Prime Minister as Chairman. The programme aims to provide eight years of quality elementary education for all children upto the age of 14 years in a Mission mode with a thrust on community ownership, disadvantaged group and girls' quality education and alternative modes of education. All existing schemes on elementary education will converge with this scheme after the Ninth Plan and it will cover all districts in the country by March, next year.

64. We are determined to maintain and strengthen our competitiveness in the field of technology education. A task force set up for this purpose under the HRD Minister has made wide ranging recommendations to upgrade and expand this area of education. The Roorkee Engineering College will be upgraded in to an IIT and funding for IIT, Guwahati has been stepped up to ensure its early completion. The base of IITs is to be expanded, regional engineering colleges are to be strengthened and new institutes will be set up with public private partnership. The role of the private sector will be encouraged. A new Centrally Sponsored Scheme for computer literacy and studies in schools is being launched and other initiatives planned for encouraging IT education from school to college levels.

65. Last year, I announced the availability of 100 per cent deduction from income tax of payments made to institutions for vocational education and training by the private sector set up in rural areas and small towns. I propose to make the same deduction available for payments to engineering institutions also.

Educational Loans for Students

66. Mr Speaker Sir, I have personally experienced poverty and faced problems in pursuing higher studies. I, therefore, feel that no deserving student

in the country should be deprived of higher and technical education for want of finances. I am glad that the Indian Banks Association (IBA) has formulated a new comprehensive Educational Loan Scheme, which will cover all courses in schools and colleges in India and abroad. Loans will be available under this scheme up to Rs 7.5 lakh for studies in India, and Rs 15 lakh for studies abroad. No collateral or margin will be stipulated for loans up to Rs 4 lakh, the interest of which will not exceed the prime lending rate (PLR). The interest rate will not exceed PLR plus 1 per cent for loans above Rs 4 lakh. The loans would be repaid over a period of 5 to 7 years with provision of a grace period. I hope that this scheme will enable needy children to pursue higher and technical studies both inside and outside India.

Women

67. The year 2001 is being observed as Women's Empowerment Year. My colleague, the Deputy Chairman of the Planning Commission is heading a Task Force to review the programmes for women. Meanwhile I propose to:

- Strengthen the Rashtriya Mahila Kosh for providing micro credit to poor assetless women through NGOs.
- Launch an integrated scheme for women's empowerment in 650 blocks through women's self help groups.
- Start a new scheme for women in difficult circumstances like widows of Vrindavan, Kashi and other places, destitute women and other disadvantaged women groups.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

68. In keeping with Government's commitment to improve the Welfare of the scheduled tribes, a separate National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation with an authorised share capital of Rs 500 crore has been set up. The allocation for the schemes for welfare of scheduled tribes in the Ministry of Tribal Affairs has been enhanced from Rs 786 crore this year to Rs 986 crore in the coming year.

69. Similarly, the allocation for the schemes for welfare and upliftment of scheduled castes in the Ministry of Social Justice & Empowerment has been enhanced from Rs 709 crore this year to Rs 790 crore in the coming year.

Social Security

70. Hon'ble Members may recall my announcement in the last budget, of a new Group Insurance Scheme, the "Janashree Bima Yojana" to extend Social Security cover to the poorest sections of society. The said scheme was launched by the Prime Minister on 10, August, 2000 and has been well received. 332 schemes have been approved so far covering 99,750 people in the BPL segment.

71. I believe that the Social Security cover needs to be widened to minimize the miseries of our people below the poverty line. Accordingly, I propose to introduce two more schemes during the next financial year:

- (i) A special scheme for landless agricultural labourers, the Khetihar Mazdoor Bima Yojana, which will provide benefits of insurance cover as available under Janashree Bima Yojana and a pension of Rs 100 per month, to the beneficiary on attaining the age of 60 years. In the case of beneficiaries who join the scheme at a young age, some periodical payments at the end of every ten years are also envisaged. The beneficiaries will be required to make a small contribution towards the premium.
- (ii) A Shiksha Sahyog Yojana, to provide an education allowance of Rs 100 per month to the children of parents living below the poverty line, to meet the expenses of education during their studies from 9th to 12th standard, so that a needy student is not deprived of the opportunity to continue his/her education for want of funds. This will be available to subscribers of the Janashree Bima Yojana.

These schemes will be managed by LIC.

72. Meanwhile, I have some good news for workers. The wage ceiling for coverage under the EPF and MP Act, 1952 has been enhanced from Rs 5000 to Rs 6500. To promote the welfare of employees I propose to enhance the ceiling for Government contribution of 1.16 per cent of monthly wage of employees to the Pension Fund from Rs 5000 to Rs 6000 per month. The extra expenditure on this account is estimated to be Rs 77 crore per annum.

73. Whereas the organised sector is at present covered by various pension, provident fund and gratuity schemes, the unorganised sector does not have adequate social security coverage. I am asking the Insurance Regulatory Development Authority to look into all these issues and provide a road map for pension reforms by October 1, 2001.

Journalists Welfare Fund

74. Journalists have to increasingly take greater risks in covering terrorist and other violence prone incidents. As an acknowledgement of their services and sacrifices, and with the expectation of a better treatment at their hands, I propose to set up a Journalists Welfare Fund with a contribution of Rs 1 crore under the grants of Ministry of I&B. My colleague the I&B Minister will announce the details of the scheme.

Entertainment

75. Our entertainment industry, particularly the film industry not only provides the much needed fantasy to millions of our people who live in an otherwise harsh and cruel world, it has also emerged as an important segment of our economy and holds great promise for the future. Two years ago, I provided for this industry the same tax exemption that was available for merchandise

exports. A few months ago, the Government issued a notification under the IDBI Act whereby entertainment industry including films has been declared as an industrial concern. Banks are in the process of finalising guidelines for financing such projects that are bankable. I hope that the film industry will take full advantage of these measures to bring about a greater degree of professionalism and transparency in its operations, and will not do things chupke chupke and certainly not chori chori.

FISCAL CONSOLIDATION

76. As I have already stated the most serious problem confronting the economy is the poor state of the fiscal health of both the Central and State Governments. The combined fiscal deficit of the two together is in the region of 10 per cent of GDP. I have often been described as a fiscal fundamentalist. Some have gone to the extent of calling me a fiscal terrorist. Why am I so concerned about the fiscal deficit? Let me try to explain. The total receipts of the Central Government in the current year according to BE are about Rs 281,000 crore. Of this amount, Rs 72,000 crore is States' share of the Central taxes and grants. The Central Government is, therefore, left with Rs 209,000 crore. On the expenditure side, about Rs 101,000 crore was to be spent on interest, Rs 59,000 crore on defence, Rs 23,000 crore on major subsidies and Rs 16,000 crore on pensions. The net amount left for meeting all other Government expenditure totalling Rs 123,000 crore was, therefore, only Rs 12,000 crore. I have, therefore, to borrow Rs 111,000 crore in the current year to make both ends meet. The most worrisome aspect is that over 70 per cent of my borrowing, i.e., Rs 77,000 crore was for financing unproductive revenue expenditure. This will add to my interest burden next year forcing me to borrow more and ultimately fall into a debt trap. I am deeply conscious of the burden which is being placed on future generations, by our extravagance. I cannot allow this situation to continue.

77. As promised in my earlier Budget Speeches, I appointed the Expenditure Reforms Commission last year and introduced the Fiscal Responsibility Bill in this House in the last session. The bill seeks to reduce the fiscal deficit to 2 per cent and completely eliminate the revenue deficit over the next five years.

78. A number of initiatives have already been taken to contain, in particular, the growth of non-plan expenditure. I have not allowed any increase in non-plan expenditure this year. Consequently, for the first time in many years, the fiscal deficit target fixed in the budget has indeed been achieved, and remains at 5.1 per cent in the RE of the current year. The target of 3.6 per cent revenue deficit has also been achieved.

Expenditure Management

79. I intend to carry forward the process of bringing about structural changes in the composition of Central Government expenditure and effect economy in non-plan revenue expenditure with greater vigour while improving the quality of plan expenditure. For this, I propose to take the following initiatives:

- User charges for services provided by government and its agencies will be revised keeping in view the increased cost of these services. A portion of this increase will be provided to enhance the maintenance and quality of these services.
- Similarly, postal rates will be revised moderately to contain the rising postal deficit.
- All requirements of recruitment will be scrutinized to ensure that fresh recruitment is limited to 1 per cent of total civilian staff strength. As about 3 per cent of staff retire every year, this will reduce the manpower by 2 per cent per annum, achieving a reduction of 10 per cent in five years as announced by the Prime Minister.
- The Surplus Pool under the Department of Personnel will be streamlined and equipped to redeploy and retrain surplus staff. Employees in the Surplus Pool will also be offered an attractive VRS package.
- Standard licence fee (rent) on government accommodation will be enhanced by 50 per cent for Group A, 25 per cent for Group B and 15 per cent for other categories of staff with effect from April 1, 2001.
- Facility of LTC to Central Government employees will be suspended for 2 years for the remaining part of the four-year block period except for employees who are entitled to last LTC before retirement.
- Use of Information Technology in government activities with large public interface will be maximized to promote efficiency. For this purpose, operations like GPF, pension, pay and accounts offices, passports, income tax, customs, central excise, will be fully computerized by March 31, 2002. Public sector banks and insurance companies are also being asked to complete computerization of their operations within this period.

80. The Expenditure Reforms Commission, which was set up last year, has presented reports concerning downsizing in 6 Ministries and Departments. These include Department of Economic Affairs, Ministry of Information & Broadcasting, Ministry of Coal, Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises and Ministry of Small Scale Industries. Reports of the Commission concerning other Departments will also be received within the next six months. These recommendations will be implemented by July 31, 2001 and identified surplus staff transferred to the Surplus Pool.

81. Charity, it is said, must begin at home. I believe austerity, too, must begin at home. To lead by example, based on the recommendations of the Expenditure Reforms Commission, I propose to abolish three secretary/special secretary level and two joint secretary level posts in the Department of Economic Affairs. This will be done in stages by 31, July. In addition, another 44 posts of directors and below will be abolished, as against 31 recommended by the ERC. 1675 posts are being abolished in the Currency and Coinage Division which will be restructured and corporatised. The National Savings Organisation is to be downsized from a level of 1191 staff to about 25. I have asked ERC to provide *their recommendations in respect of the Departments of Revenue and Expenditure also*. I am confident that this will expedite the process of right sizing the establishments in all the Ministries/Departments of Government.

82. The Planning Commission has commenced the task of preparing the Tenth Plan. Given the severity of resource constraints, improvement in the quality of government spending is of the essence. It has therefore been decided to subject all existing schemes, both at the Central and State levels, to zero based budgeting and to retain only those that are demonstrably efficient and essential. Furthermore, all schemes that are similar in nature will be converged to eliminate duplication. Centrally sponsored schemes that can be transferred to States will be identified. Resource flows will be linked to performance. Necessary procedural changes will also be made to speed up the decision making process for approval of schemes. Utmost importance will be given to decentralized planning.

Pension Reforms

83. The Central Government pension liability has reached unsustainable proportions: as a percentage of GDP, it has risen from about 0.5 per cent in 1993-94 to 1 per cent in 2000-2001. As such it is envisaged that those who enter central government services after October 1, 2001 would receive pension through a new pension programme based on defined contributions. In order to review the existing pension system and to provide a roadmap for the next steps to be taken by the Government, I propose to constitute a High Level Expert Group, which would give its recommendations within 3 months.

Interest Rates

84. I have drawn your attention to the increasing share of debt service burden in the expenditure budget caused by rising government debt and exacerbated by the prevalence of high real interest rates. Most interest rates in the economy are now market determined. But, their movement downward is constrained by the rigidities inherent in the administered interest rates governing the contractual saving sphere i.e. Provident Fund and Small Savings Schemes. I have examined this issue very carefully. I find that the interest rates provided in all these schemes seldom exceeded consumer price inflation by more than

3 per cent between 1980 and 1998. Since then, this difference has risen to 6 to 8 per cent. Not only are such high real interest rates putting an unsustainable burden on both Central and State Governments but the resulting high cost of capital is also inhibiting economic growth all round. I am therefore reducing most administered rates by 1.5 per cent as of March 1, 2001. Government guarantee and tax incentives for these schemes will continue. For the future, I propose to explore a better system for the determination of these rates. I propose to appoint an Expert Committee to provide recommendations on this issue.

85. The benefit of reduction in interest rates on Small Savings Deposits will be fully passed on to the States. This will reduce their borrowing cost from Small Savings by 100 to 150 basis points. In addition, I am also reducing the interest rate on loans portion of Central assistance to State Plans by 50 basis points. Alignment of interest rates on GPF by the State Governments along with the reduced provident funds interest rates at the Centre will further reduce the interest burden of State Governments. Moreover, because of the anticipated increase in gross tax collection of the Centre, devolution of central taxes to States is expected to increase by over Rs 9000 crore in 2001-02 over the current year. All these measures will help in reducing the debt burden of the States and improve their fiscal position.

State Fiscal Reforms

86. Along with fiscal consolidation at the Centre, it will be our endeavour to work jointly with the States to reform their finances. Pursuant to the recommendations of the Eleventh Finance Commission, an Incentive Fund of Rs 10,607 crore has been earmarked for the next 5 years to encourage States to implement monitorable fiscal reforms. These reforms will essentially be the States' own programmes and considerable flexibility has been provided for individual States to design their programmes. In the fiscal year 2001-02, I have provided an amount of Rs 4243 crore towards this Incentive Fund.

PUBLIC SECTOR RESTRUCTURING AND PRIVATIZATION

87. Our public sector has expanded in almost every area of economic activity. In many ways, it has served the nation well; capability has been developed all round and a strong industrial base built up. These enterprises must now be strengthened to compete and prosper in the new environment. Last year I had defined government's policy in this regard clearly.

88. Financial and business restructuring plans of a number of PSUs including SAIL and HMT have been approved. Since 1998 financial restructuring support to viable and potentially viable PSUs amounting to more than Rs 13,000 crore has been provided to 23 PSUs. Government has also decided to close

down 8 non-viable PSUs during the current year. A package of measures for revival and closure of the various mills of National Textiles Corporation has also been approved.

89. The procedure for privatization of public sector enterprises has now been considerably streamlined. The Department of Disinvestment has been set up to accelerate the privatization process. To maximise returns to government, our approach has shifted from the disinvestment of small lots of shares to strategic sales of blocks of shares to strategic investors. The Government has already approved privatization of 27 companies in which the process of disinvestment is expected to be completed during the course of the year. These companies include among others VSNL, Air India, and Maruti Udyog Limited.

90. Given the advanced stage of the process of disinvestment in many of these companies, I am emboldened to take credit for a receipt of Rs 12000 crore from disinvestment during the next year. An amount of Rs 7000 crore out of this will be used for providing restructuring assistance to PSUs, safety net to workers and reduction of debt burden. A sum of Rs 5000 crore will be used to provide additional budgetary support for the Plan primarily in the social and infrastructure sectors. This additional allocation for the plan will be contingent upon realization of the anticipated receipts. In consultation with Planning Commission I shall come up with sectoral allocation proposals during the course of the year.

GUJARAT EARTHQUAKE

91. The earthquake in Gujarat has been a terrible and unprecedented tragedy in terms of loss of life and damage to property. Although I am confident that the inherent resilience and entrepreneurial spirit so characteristic of the people of Gujarat will result in quick restoration of economic activity, I would like to assure the House that we have the capacity to fully meet the challenges of such natural calamities without deflecting from our path of pursuing our economic goals.

92. To enable the State Government to deal with the situation, Government of India is extending the following assistance:

- Rs 500 crore was made available to the State immediately from the National Calamity Contingency Fund.
- The National Calamity Contingency Fund, set up with initial corpus of Rs 500 crore as a result of the Eleventh Finance Commission recommendations, is being augmented by the imposition of a 2 per cent surcharge on personal income tax and corporate tax.
- Assistance will be provided to the State Government under various Centrally Sponsored Schemes for reconstruction of roads, bridges, power installations, school buildings, public utilities and other public infrastructure.

- Arrangements have been tied up with the World Bank and Asian Development Bank for obtaining a line of credit of US \$ 800 million. A joint team has already visited Gujarat and substantial additional funds are expected to be negotiated.
- RBI has instructed banks to make special arrangements for freezing of recoveries and extension of new loans on a liberal terms for borrowers in the affected areas.
- The National Housing Bank and HUDCO have set apart adequate funds for housing reconstruction. I also propose to allocate a special quota of tax free bonds of the order of Rs 2000 crore between the two institutions.
- As was done after the Orissa cyclone, cement and steel used for construction in the Indira Awas Yojana, by HUDCO and by agencies identified by the State Government, would be exempt from excise duty.
- The Government of Gujarat will be enabled to raise funds by floating tax free earthquake relief bonds which will be open to subscription in Rupees to individuals and others including Non-Resident Indians through the Reserve Bank of India.
- All goods intended for relief have been exempted from excise and customs duties; direct tax assesseees have been given extension of time for filing their returns.

93. A natural calamity of this magnitude has also highlighted the need to set up permanent institutional arrangements for management of national disasters. The National Committee on Disaster Management under the Chairmanship of Prime Minister will be making recommendations for laying down effective long term strategy for this purpose.

BUDGET ESTIMATES

Revised Estimates for 2000-2001

94. We have been able to adhere to the Budget target of fiscal deficit despite pressures on public finances on account of deceleration in disinvestment programme, natural calamities and the relief to consumers of petroleum products. The revised estimates for the current fiscal year show a marginal decrease in expenditure of Rs 2,965 crore as compared to the Budget estimates.

95. Net tax revenues for the Centre are estimated to be Rs 1,44,403 crore compared to the Budget estimates of Rs 1,46,209 crore, thereby reflecting a shortfall of Rs 1806 crore. The shortfall is mainly due to lower collection of Customs and Union Excise duties which were reduced to provide relief to POL consumers. Non tax revenue is estimated at Rs 61,763 crore, Rs 4299 crore more than the estimated level of Rs 57,464 crore. However, disinvestment receipts are expected to be lower at Rs 2500 crore against the Budget target of Rs 10,000 crore.

96. The fiscal deficit as a percentage of the GDP is expected to be on target at 5.1 per cent.

Budget Estimates for 2001-2002

97. In the budget estimates for 2001-2002, the total expenditure is estimated at Rs 3,75,223 crore, of which Rs 100,100 crore is for plan and Rs 275,123 crore for non-plan.

Plan Expenditure

98. The budget support for Central, State and UT Plans has been placed at Rs 100,100 crore, an increase of Rs 13,862 crore over revised estimates 2000-2001. This amounts to an increase of 16 per cent. Gross budgetary support for the Central Plan is being enhanced from Rs 48,269 crore in the revised estimates 2000-2001 to Rs 59,456 crore in 2001-2002. Central Plan assistance to States and Union Territories in 2001-2002 is also proposed to be increased to Rs 40,644 crore from Rs 37,969 crore in the revised estimates 2000-2001.

Non Plan Expenditure

99. Non-plan expenditure in 2001-2002 is estimated to be Rs 2,75,123 crore compared to Rs 2,49,284 crore in Revised estimates for 2000-2001. The increase in non-plan expenditure is mainly in interest payments (Rs 11,633 crores), defence (Rs 7,539 crore) and Grants to State Governments (Rs 2,221 crore).

100. In order to practice greater accountability and transparency, I am attaching with the budget papers this year a new report on "Implementation of Budget Announcements, 1999-2000 and 2000-01".

PART B

101. Sir, I now present my tax proposals, indirect taxes first.

102. In my earlier budgets, I have endeavoured to ensure a continuity of approach in framing my revenue proposals. The principles that have guided me have been the need for growth in revenues, simplification and rationalization of the tax regime, and effective tax compliance through measures, which are friendly for the honest taxpayer, and a deterrent to the evader. I have reduced the number of rates in both customs and excise duties, simplified procedures and introduced measures to improve tax compliance. I have given up my discretionary power to grant excise and customs duty exemptions in individual cases thus saving hundreds of crore of revenue for Government. The policy of penalties against tax evaders has also been made non-discretionary. With all these steps I have sought to put an end to a system that pressure groups or lobbies could influence. My attempt this year is to take this process to its logical conclusion.

103. In my last budget, I had introduced the rate of 16% as the rate of Central Value Added Tax (CENVAT). I had also rationalized the rates of special excise duty to three, namely, 8%, 16% and 24%. The single rate of CENVAT now contributes about 68% of the total excise revenues from *ad valorem* duties.

104. I now propose to reduce the three rates of special excise duty to a single rate of 16%. As a consequence, I propose to abolish the 8% special excise duty on the following items:

- (1) Glazed tiles
- (2) Mattresses and articles of bedding
- (3) Carpets and floor coverings
- (4) Painted canvas, studio back cloth, etc

- (5) Linoleum and textile wall coverings etc.
- (6) Scooters and motorcycles, and
- (7) Taxis

These items will now be charged to CENVAT only at the rate of 16%.

105. White cement and other special cements, yachts and pleasure boats, arms and ammunition for private use and articles of fur skins, will attract SED of 16% and a total duty of 32%.

106. The special excise duty on aerated soft drinks, soft drink concentrates supplied to vending machines, and motorcars will be reduced to 16%, thus putting an end to the rate of 24% special excise duty. These items also will now bear a total duty of 32%. There will be no change in respect of products, which already attract this rate of 32%.

107. There are a few items that currently attract CENVAT at half the rate, namely, 8%. All these items will henceforth be charged to the normal rate of 16% except cotton yarn including sewing thread, LPG, kerosene and diesel engines up to 10 HP, which I am leaving at 8% for the present in the larger public interest.

108. After these rationalization measures about 80% of the revenue in respect of ad valorem duties will come from the single rate of 16% and about 17% from the combined rate of 32%.

109. India is the world's second largest producer of fruits and vegetables. However, most of these are wasted in the absence of proper storage and processing facilities. Food-processing industry dealing in perishable fruits and vegetables needs special support. I, therefore, propose to exempt food preparations based on fruits and vegetables completely from excise duty. This will include a very wide range of products of common use like pickles, sauces, ketchup and juices, etc. This, along with the support I have given to creation of better storage facilities will give a fillip to the food processing industry and will go a long way in improving the rural economy of our country.

110. The Eleventh Finance Commission has recommended a special levy for the replenishment of the National Calamity Contingency Fund. As an *ad hoc* measure, this was provided for in the current year through a special surcharge on corporate taxes. I propose to establish this funding on a regular basis through a special surcharge of excise on a range of products the use of which should be discouraged on health grounds. I propose to levy a surcharge of 15% on cigarettes. The duty on *biris* would increase from Rs 6 to Rs 7 per thousand *biris*. The total duty on *pan masala* would be 55%/60%. Miscellaneous tobacco products like chewing tobacco would be charged to a total duty of 60%.

111. Excise duty on High Speed Diesel was reduced from 16% to 12% in September last year. I propose to restore it to the normal CENVAT rate of 16%. I also propose to restore special excise duty on motor spirit to the previous rate of 16%. The burden of increase in duty is not proposed to be passed on to the consumers except for any technical corrections.

112. LPG is charged to excise duty at 8%. I propose to apply the same rate of duty to Compressed Natural Gas, which is exempt at present.

113. A special scheme of charging excise duty from independent textile processors on compounding basis was introduced in December 1998. The working of this scheme has resulted in serious distortions. I have therefore decided to revert to the *ad valorem* duty structure for independent textile processors with effect from 1, March 2001. Independent processors would be allowed to take CENVAT credit of the duty paid on inputs on a deemed basis.

114. There is no economic logic to continue with excise duty exemption on garments sold under a registered trade name. I propose to impose a duty of 16% on such garments.

115. Products of SSI units are exempt from excise duty up to Rs one crore. This exemption is intended to provide fiscal support to the genuinely small producers. I propose to withdraw this exemption in respect of the following items, in which misuse of the exemption is more than likely:

- ★ Cotton yarn
- ★ Ball or roller bearings
- ★ Arms and ammunition for private use

116. The excise duty structure on matches comprises rates of duty ranging from 25 *paise* to Rs 2.40 per hundred boxes of 50 sticks each. I propose to rationalise the existing rates to a more rational structure with a duty rate of 50 *paise* for the handmade sector, Re.1 for the middle sector, Rs 2 for the semi-mechanized sector and Rs 3 for the mechanized sector.

117. Mr. Speaker, Sir, in the matter of rates of duties of excise I have almost achieved the ultimate with only one basic rate of CENVAT and one rate of special excise duty. The procedures in excise have also been made modern. I can humbly claim that excise duty is now a model of value added tax up to the manufacturing stage.

118. The only issue, which remains to be tackled now, is the issue of individual exemptions. The regime of exemptions is incompatible with a simple, equitable and rational tax structure that has now been put in place. I am not doing away with the exemptions altogether, realizing that this may come as a sudden shock to those who are accustomed to exemptions. However, I will like

to give notice to them to be prepared to pay duties like anyone else. For the present, I am making a modest beginning by imposing a nominal duty of 4% on some items like goggles, imitation jewellery, rubberized mattresses etc. which in four equal annual installments will be taken to 16%. More and more items will be put on this escalator every year.

119. Structural changes have taken place in the economy with the service sector growing faster than other sectors. I am expanding the net of service tax and I propose to add the following services to the list of taxable services:

- Specified Banking and Financial Services
- Authorized Service Stations for servicing of vehicles including two wheelers
- Port Services
- Broadcasting Services
- Photographic Services
- Convention Services
- Sound Recording Services
- Scientific and Technical Consulting Services
- Telex Services
- Telegraph Services
- Facsimile Services
- On-line Information & Data Base Retrieval services
- Video Tape Production Services
- Services auxiliary to Insurance

120. I propose to bring the service provided to lease circuit line holders also in the tax net.

121. I now turn to my proposals relating to customs duties.

122. In my previous budgets, I have reduced the total number of major customs duty rates to four, that is, 35%, 25%, 15% and 5%. I do not wish to propose any further reduction in the number of customs duty rates this year. However, I propose to discontinue the surcharge of 10%. With this, peak level of customs duty will decline marginally from 38.5% to 35%.

123. All agricultural produce already attracts the peak rate of duty of 35% or more. Current tariffs on major cereals are: Wheat (50%), Rice (70%/80%) and Maize (50%). I now propose to increase the customs duty on tea, coffee, copra, and coconut and desiccated coconut from the present 35% to 70%.

124. Similarly, I propose to increase the rate of duty on crude edible oils ranging from 35% to 55% at present to a uniform rate of 75% and on refined oils from 45%/65% to 85%. A lower rate of 45% would apply to soyabean oil on account of WTO binding. I also propose to enhance the rate of customs duty on the import of crude palm oil by *vanaspati* manufacturers from 25% to 55% and restrict this concession to sick *vanaspati* units only. The others will pay 75%. I wish to assure the House that in order to safeguard the interest of our farmers we shall move swiftly whenever any perceptible threat on account of imports is noticed.

125. The House is aware that Government has committed itself to abolish customs duty on IT and telecom products and their inputs and components under the ITA 1 Schedule by 2003. The customs duty on these products is proposed to be reduced to 15% from 1, March 2001 from current levels.

126. Mr. Speaker, Sir, with the abolition of the remaining Quantitative Restrictions in April this year second hand cars will also become freely importable. To allay the fears of surge in import of second hand cars, the rate of basic customs duty on their import will be raised to 105%, which is three times the peak rate. The total duty now applicable to second hand cars will be more than 180%. I propose a similar structure of duty for the import of old multi utility vehicles, scooters and motor cycles.

127. In order to provide a level playing field for domestic liquor producers, I propose to levy CVD at a suitable rate on imported liquor, taking into account the levies of state excise on domestic production.

128. Our textile industry has to modernize itself and acquire the latest technology in order to face global competition and attain high quality of production. I propose to reduce the basic customs duty on specified textile machines, including shuttle-less looms, from 15% to 5%. As a measure of further relief to the textile sector, I propose, to reduce the customs duty on silk waste, cotton waste and flax fibre from 35% /25% to 15%.

129. There are some cases of anomaly in customs duty between raw materials and intermediate goods on the one hand, and intermediate goods and final products on the other. DMT, PTA, MEG and Caprolactum are raw materials for production of man-made fibers and yarns. However the customs duty on these materials is higher than the rate applicable to fibers and yarn. I propose to reduce the customs duty on DMT, PTA, MEG and Caprolactum from 25% to 20%, which is the WTO bound rate for synthetic fibers and yarns.

Similarly, soda ash is an input for the production of glassware, detergents etc. and currently attracts the peak customs duty of 35% along with the final products. I propose to reduce it to 20%. I also propose to reduce the customs duty on polyester chips and nylon chips for the manufacture of fibers and yarns from 35% to 25%.

130. On the same analogy, the customs duty on high quality DBM, seawater magnesia and fused magnesia is being reduced from 25% to 15%.

131. Gems and jewellery have considerable potential for export. I propose to reduce the customs duty on cut and polished coloured gem stones from 35% to 15%. I also propose to reduce the customs duty on specified equipment when imported by training institutes sponsored by the Gem and Jewellery Export Promotion Council from 25% to 15%. The rate of customs duty on rough diamonds would now be 5%.

132. CNG kits and their parts attract low duty at 5%. I propose to extend the same treatment to LPG conversion kits and their parts.

133. LNG is not produced in India. The burden of CVD on the import of LNG adds to the cost of LNG projects. I therefore propose to exempt LNG from CVD.

134. For the same reason, I also propose to exempt wattle extract from the application of CVD.

135. I propose to reduce the customs duty on cement, and clinkers from 35% to 25%. I am confident that this reduction would help softening of domestic prices of cement for the benefit of consumers.

136. Mr. Speaker, Sir, accredited pressmen and cameramen are allowed to import cameras, computers, fax machine etc. up to a value of one *lakh* rupees for their professional use without payment of customs duty once in five years. In view of many good photographs they have taken of use, I propose to reduce this long waiting period from five years to two years.

137. In order to encourage better quality of cinematography I propose to reduce the customs duty on cinematographic cameras, projectors and certain other related equipment used by the film industry from 25% to 15%.

138. In order to discourage smuggling I propose to reduce the duty on gold from Rs 400 per 10 grams to Rs 250 per 10 grams.

139. Several industry associations have pointed out that the CVD on the imported consumer products should also be charged on the basis of maximum retail price; otherwise it does not provide a level playing field. I accept the logic of their argument. The Finance Bill contains the enabling provision to implement this decision.

140. I propose to withdraw the exemption from customs duty on a few items and impose on them a nominal duty of 5%.

141. I have already promised that our customs tariff would be brought down to East Asian levels. I will like to move progressively within three years to reduce the number of rates to the minimum with a peak rate of 20%. The modalities for this will be worked out in time for the next budget.

142. Sir, a number of steps are also being taken for greater procedural and administrative efficiency.

143. A new Manual of Procedures and Instructions on Central Excise and Customs would be brought out by 1, September 2001. The emphasis would be on simplicity, brevity and transparency. I also propose to simplify the central excise rules to make them user friendly.

144. My proposals on the excise side are estimated to result in a revenue gain of Rs 4677 crore in a year. On the customs side my proposals are estimated to result in a revenue loss of Rs 2128 crore. I estimate that the indirect tax revenue next year would be Rs 1,40,992 crore.

145. Copies of the notifications issued to give effect to the changes in excise and customs duties shall be laid on the Table of the House in due course.

146. In Direct Taxes, my thrust during the last three years has been on providing stability of tax rates, widening the tax base, rationalizing and simplifying the tax laws and giving impetus to economic growth. These efforts have resulted in increasing the direct tax revenue from Rs 46,428 crore in 1998-99 to an estimated Rs 74,467 crore this year. In addition, the number of assessees has increased significantly from a little over one crore in March 1998 to 2.3 crore at the beginning of this year. I, therefore, propose to continue with the same rates this year also. Co-operative Societies, however, will henceforth pay 30% tax instead of 35%.

147. While imposing the surcharge of 10 % on corporates and non-corporates in my budget of 1999-2000, I had promised that this would be a temporary levy. However, I was constrained to increase the surcharge on non-corporate tax payers at the higher income levels to 15% due to the unexpected expenditure burden of Kargil. During the course of this financial year I had further levied a surcharge of 1% on corporates towards the National Calamity Contingency Fund and an additional 2% on all tax payers for the Gujarat Earthquake relief. I now propose to remove all surcharges payable by corporates and non-corporates except the surcharge of 2 % for relief to quake hit areas of Gujarat. Individuals having an income of up to Rs 60,000/- will not be subject to this surcharge.

148. As a welfare measure, Sir, I propose to allow 100% deduction for donations to the National Trust for welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities.

149. Hon'ble Members are aware that the modified one-by-six scheme, which I introduced in the Finance Act, 1998 to identify potential income-tax assesseees and to bring them into the tax net, has paid rich dividends. I, therefore, propose to extend the one-by-six scheme to all urban areas in the country as defined by the 1991 Census. Changes arising out of the 2001 census will be incorporated subsequently.

150. Certain companies are not filing their returns of income, presumably on the plea that they are not having any taxable income. These companies go out of fiscal discipline and their financial transactions during the initial years escape scrutiny. I therefore, propose that all companies should file their returns even if they incur a loss.

151. Sir, another effective measure of widening the tax base is to further enlarge the scope of deduction of tax at source. Income tax at source will henceforth be deductible at the rate of 10 % on income by way of commission or brokerage exceeding Rs 2,500/-, except on transactions relating to shares and securities.

152. Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. are currently taxed at 40%. As the marginal personal income tax rates have now stabilized at 30%, this income will also now be taxed at 30%. Television game shows are very popular these days. I wish the winners well. At the same time, I propose that income tax at the rate of 30% will be deducted at source from the winnings of these and all similar game shows.

153. At present, tax is deducted at source on income from interest on time deposits only if such income exceeds Rs 10,000/- in respect of deposits with a Bank or Housing Finance Company and Rs 5,000/- in other cases. These threshold limits have led to the erosion of tax base and under-reporting of taxable income due to splitting up of deposits. I, therefore, propose to lower this limit to Rs 2,500/- in all cases.

154. With economic liberalization, the pay package of salaried class is undergoing many changes. It is being divided into various components and the forms of perquisites and benefits or amenities provided by the employers are assuming new dimensions. To align our tax system with the present structure of pay packages, I propose that the value of perquisites, benefits or amenities shall be determined on the basis of their cost to the employer, except in respect of houses and cars where different criteria will be adopted for simplicity.

155. Sir, I also propose to provide relief to salaried persons in the lower income range having income up to rupees one lakh. Such persons will get an

enhanced tax rebate at the rate of 30% in respect of their eligible investments under section 88 of the Income Tax Act, as against 20% at present.

156. In the case of Export Oriented Units, and units located in Export Processing Zones, Free Trade Zones and Software Technology Parks 25% of their sales in the domestic market are currently tax exempt. I propose to provide for the taxation of profits from these domestic sales of such units.

157. I.T. Sector continues to do well and should be encouraged to do better. I, therefore, propose that profits derived by the units located in the software technology parks from the export of "on-site" services will be eligible for deduction like their other export income. Units located outside these zones will also get the benefit of tax exemption on such export earnings. I further propose that the condition relating to transfer of ownership of companies in sections 10A and 10B of the Income-tax Act shall not apply in respect of companies in which public are substantially interested.

158. The income of NABARD, National Housing Bank and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) was exempted from tax in order to provide fiscal support in the initial years of their functioning. Now these institutions have come of age and are working on commercial lines. I, therefore, propose to withdraw the tax exemption available to these institutions.

159. The interest payable on certain External Commercial Borrowings (ECBs) is currently exempt from tax. Having regard to the fact that interest received by the lender is taxable in the country of his residence and he would get a credit for any tax paid by him in India, any exemption from tax liability in the host country does not benefit the lender but only results in reducing our tax revenues. I, therefore, propose that the tax exemption in respect of interest paid on such External Commercial Borrowings will not be available for such borrowings made on or after the first day of June 2001.

160. Certain interest income up to a limit of Rs 12,000 is deductible at present under section 80L. In addition, income from Government securities is also deductible up to Rs 3,000. I propose to reduce the maximum limit of this deduction to Rs 9,000.

161. The tax payable on the distribution of dividends of domestic companies and income in respect of Units of Mutual Funds and UTI was increased from 10% to 20% last year. To provide a stimulus to the growth of capital market, I propose to reduce this tax to 10%.

162. To help revive investor-interest in primary issues I propose to exempt long-term capital gains arising from the sale of securities and Units if such gains are reinvested in primary issues of shares of public companies.

163. Sir, the tax incentives in the form of tax holidays for infrastructure facilities are proposed to be further rationalized and enlarged. For the core sectors of infrastructure namely, roads, highways, rail system, water treatment and supply, irrigation, sanitation and solid waste management systems, I now propose a ten-year tax holiday which may be availed of during the initial twenty years. In the case of airports, ports, inland ports and waterways, industrial parks and generation and distribution of power, which also become commercially viable only in the long run, a tax holiday of ten years is being proposed to be availed of during the initial fifteen years. The period of commencement of business for power and industrial parks is also being extended up to 31, March 2006.

164. The five-year tax holiday and 30 % deduction for next five years was available to the telecommunications sector till 31, March 2000. I propose to reintroduce this concession retrospectively for the units commencing their operations on or before 31, March 2003. These concessions will also be extended to internet service providers and broadband networks.

165. Sir, in addition to the tax holiday proposed for development of infrastructure, tax incentives have also been provided for the investors providing long-term finance or investing in the equity capital of the enterprises engaged in infrastructure facility. Any income by way of interest, dividends or long-term capital gains from such investments is fully exempt. I propose to extend this concession to guarantee commissions and credit enhancement fees earned by financial institutions from infrastructure enterprises. Co-operative Banks will also be eligible for exemption of their income from investments in approved infrastructure facilities.

166. To be globally competitive, our companies need to increase their investment and expenditure for Research and Development. Currently, a weighted deduction of 150% of the expenditure on in-house research and development in certain areas is allowed to companies. Sir, I propose to extend this weighted deduction to biotechnology as well for clinical trials, filing patents and obtaining regulatory approvals. I also propose that the entire amount paid to specified projects under the India Millennium Mission, 2020 will be eligible for 125 % weighted deduction.

167. To encourage development of industrial infrastructure, I had provided 100% deduction of export profits for a period of ten years to units operating in the Special Economic Zones last year. I now propose to give further tax incentives for the development of these zones. The concessions

available for infrastructure by way of a 10-year tax holiday will be available to the developers of Special Economic Zones on the same lines as developers of industrial parks. The income of investors making long term investment for the development of SEZs will also be exempt.

168. The storage of food grains and their transportation are our major concern. Sir, I propose to provide a tax holiday for five years and 30% deduction of profits for the next five years to the enterprises engaged in the integrated business of handling, transportation and storage of food-grains.

169. Sir, for promoting the industry that provides the 'cup that cheers', I propose to increase the development allowance available for tea from 20% to 40%. This additional allowance will be used only for re-plantation, rejuvenation, and modernization of tea plantations and processing facilities.

170. There has been a long-standing demand from the Shipping Industry that the rate of depreciation available in respect of ships and inland water vessels may be increased. I propose to increase this rate of depreciation to 25%.

171. To encourage investments in weaving, processing and garment sectors of the textile industry, I propose to allow accelerated depreciation at the rate of 50% on plants and machinery purchased under the Technology Up-gradation Fund Scheme.

172. In order to give a boost to the commercial vehicles sector presently facing recession, I propose to allow accelerated depreciation at the rate of 50% on new commercial vehicles for one year.

173. Each of my past three budgets has provided for increasing tax incentives for the housing sector. Sir, continuing with this practice, I propose to further increase the maximum amount of deduction available for interest payable on housing loans for self-occupied houses from rupees one lakh to rupees one and a half lakhs.

174. For persons having income from house property, the present deduction of 25 % of annual value for repairs etc. is proposed to be enhanced to 30%. However, there will be no further deductions, except for the expenditure incurred by way of interest payment on housing loans.

175. I propose to extend the tax incentives allowed by way of deduction or rebate on payments of LIC premium to all insurance companies that have been approved by the Insurance Regulatory and Development Authority

176. The presence of multinational enterprises in India and their ability to allocate profits in different jurisdictions by controlling prices in intra-group transactions has made the issue of transfer pricing a matter of serious concern. I had set up an Expert Group in November 1999 to examine the issues relating to transfer pricing. Their report has been received, proposing a detailed structure for transfer pricing legislation. Necessary legislative changes are being made in the Finance Bill based on these recommendations.

177. The foreign telecasting channels will henceforth be taxed in India, on their income computed in accordance with the provisions of the Income-tax Act.

178. Sir, I propose to bring about a number of measures that will be friendly to the taxpayer. The time limits for issue of refunds, reassessment and reopening of assessments by the Income-tax Department are proposed to be reduced. The Department will also no longer have power to withhold the refund due to an assessee. Similarly, there will be no requirement to obtain a Tax Clearance Certificate under section 230A from the Assessing Officer before transfer of immovable property. I also propose to remove the discretion presently available in deciding the quantum of penalties. Henceforth, a fixed amount of penalty will be leviable for most of the defaults.

179. Certain educational and medical institutions are required to be approved for claiming tax exemption. At present, these institutions have to file their application for approval to the Central Board of Direct Taxes. Sir, I propose to delegate this power to Chief Commissioners of Income-tax.

180. To sum up, Sir, my proposals made in this Budget on the Direct Taxes will result in a revenue loss of Rs 5,500 crore, which I propose to make up with tax buoyancy and increased voluntary compliance. I estimate that the direct tax revenue in 2001-2002 would be Rs 84,800 crore.

181. Mr. Speaker, Sir, with these proposals I estimate total tax revenue receipts for the Centre at Rs 163031 crore and the fiscal deficit at Rs 116314 crore or 4.7% of GDP. I could have managed a lesser fiscal deficit but that would have been possible only at the cost of growth, which was unacceptable.

182. This is a budget for carrying forward the second generation of economic reforms. This is a budget for growth. This is a budget for equity with efficiency. This is a budget for a new deal to the people of India in the new millennium.

183. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the budget to this august house.

D. SWARUP, Jt. Secy. (Budget)

